

संक्षिप्त



अरविंद केजरीवाल तिहाड़ भेजा गया 15 अप्रैल तक जेल

नई दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। >>पृष्ठ 2

मलयालम लेखक छोड़ देता है साहित्य अकादमी

नई दिल्ली मलयालम लेखक सी. राधाकृष्णन ने सोमवार को साहित्य अकादमी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया

Advertisement for PLUTUS IAS featuring ZOOLOGY OPTIONAL and contact information.

केंद्र और कांग्रेस में तकरार कोई दंडात्मक कार्रवाई खत्म नहीं कांग्रेस के खिलाफ टैक्स नोटिस चुनाव के मद्देनजर: आईटी विभाग

प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर ने द्वीप के प्रति उदासीनता और इसके अधिकार छोड़ने के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों की आलोचना की; विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार के 2015 के आरटीआई जवाब का हवाला दिया

द्विद्व बयान नई दिल्ली उन्होंने विवाद किया- 1974 में कच्छातीव द्वीप को श्रीलंका में कब्जा करने का मामला सोमवार को उस समय बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर समाचार रिपोर्ट पेश की और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घोषणा की कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने इसमें भारतीय शेरमैन के अधिकारों को छीन लिया था।

The Congress and DMK raised the issue in Parliament as if they bear no responsibility for it, while they are the parties which did it S. JAISHANKAR, External Affairs Minister

Will Foreign Minister Mr. Jaishankar please refer to the RTI reply dated 27-1-2015... the reply justified the circumstances under which India acknowledged that a small island belonged to Sri Lanka P. CHIDAMBARAM, Congress leader

समझौते पर दोबारा गौर करना एक ect संबंध हो सकता है: पूर्व राजनयिक नई दिल्ली 1974 के भारत-श्रीलंका समझौते पर फिर से विचार करने के लिए सरकार का कोई भी कदम कच्छातीव द्वीप क्षेत्र पर भारत के संबंधों पर व्यापक राजनयिक प्रभाव डाल सकता है और अन्य दृष्टिकोणों के संदर्भों पर सवाल उठा सकता है

"कर आतंकवाद" के आरोपों के बीच, आय कर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह कोई भी "जबरदस्ती कदम" नहीं उठाने का संकल्प है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मार्च में उठाई गई लगभग ₹3,500 करोड़ की कर मांगों पर कांग्रेस के खिलाफ।

Poll respite I-T Dept. submits in SC that the Congress need not have any apprehensions over tax demands till July due to upcoming polls. Total tax demand made of Congress amounts to ₹3,567 crore.

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई की शुरुआत में, सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा कि "चूंकि चुनाव चल रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई समस्या पैदा हो... हम किसी को नहीं लेंगे।" 24 जुलाई, 2024 को मामले की दोबारा सुनवाई होने तक कठोर कदम उठाए जाएंगे।

घटनाओं के अपरत्याशित मोड़ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुश्किल था गया आयकर विभाग के ताजा नोटिस से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए ₹1,745 करोड़ की कर मांग बढ़ाना।

2014-15 से संबंधित ताजा कर नोटिस (₹663 करोड़), 2015-16 (लगभग ₹664 करोड़) और 2016-17 (लगभग ₹417 करोड़)। अधिकारियों ने मार्च 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट को समाप्त कर दिया था और पार्टी की सकल प्राप्ति पर कर लगाया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा, "उन्होंने (मेहता) मुझे निःशब्द कर दिया है..."

नवीनतम नोटिस के साथ, विभाग ने कांग्रेस से कुल 3,567 करोड़ रुपये की कर मांग की थी।

जारी रखा >>पृष्ठ 10



दूसरा उच्चतम संग्रह जीएसटी राजस्व पर असर ₹1.78 लाख करोड़। मार्च में व्यापार >>पृष्ठ 13



शिकार के लिये दबे पाँव घूमना रॉयलस की प्रचंड जीत में बोल्ट, चहल स्टार रहे खेल >>पृष्ठ 15

इजरायली हवाई हमला ईरानी को नष्ट कर देता है सीरिया में वाणिज्य दूतावास

संबंधी परेस दमिश्क



सीरियाई राज्य मीडिया ने सोमवार को कहा कि एक इजरायली हवाई हमले ने सीरिया में ईरान के दूतावास के कांसुलर खंड को नष्ट कर दिया है, जिसमें एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य सलाहकार की मौत हो गई है। ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर हमला, सीरिया में ईरानी सैन्य अधिकारियों और सहयोगियों को इजरायली सेना द्वारा लगातार निशाना बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, जो 7 अक्टूबर को गाजा में हमला के साथ युद्ध की शुरुआत के बाद से तेज हो गई है। इजरायल, जो शायद ही कभी सलीकार करता है ऐसे हमलों पर उसने कहा कि सीरियाई मीडिया रिपोर्टों के बारे में उसकी कोई टिप्पणी नहीं है।

सोमवार को सीरिया के दमिश्क में बचावकर्मी कार्रवाई में। गोज राज्य टेलीविजन अल-आलम और पैन-अरब टेलीविजन स्टेशन अल-मायादीन, जिसके सीरिया में पत्रकार हैं, ने कहा कि हमले में ईरानी सैन्य सलाहकार जनरल अली रेजा जहदी की मौत हो गई, जिन्होंने 2016 तक लेबनान और सीरिया में कुलीन कुदूस बल का नेतृत्व किया था। ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने कहा कि कम से कम सात लोग मारे गए। शरी अकबरी ने हमले का "उसी परिमाण में" बदला लेने की कसम खाई।

ईरानी अरबी-लान-

देरी के कारण फंसे हुए विमान में यात्रियों को थका देने वाले इंतजार से बचाने के लिए नया नियम

जागतिक चंद्रा नई दिल्ली



खराब मौसम जैसे कारणों से होने वाली लंबी देरी के कारण कई बार एयरलाइंस को यात्रियों को विमान के भीतर 12 घंटे तक रोककर रखना पड़ता है और टेक-ऑफ के लिए अपनी बारी का जमीन पर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यह जल्द ही बदलने वाला है।

अधिक आसानी: नए प्रोटोकॉल के अनुसार, जो यात्री विमान से उतर चुके हैं, वे परस्थान द्वार पर सुरक्षा जांच से गुजर सकते हैं। और.बी. मूर्ति

हवाई यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधार है, जो उनकी सुविधा सुनिश्चित करना चाहता है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने हवाई अड्डों और एयरलाइंस के लिए नए मानक जंचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किए हैं।

बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा जांच से गुजरने के लिए टर्मिनल भवन में वापस जाएं यदि आठ में देरी हो तो स्वयं या तो मौसम या तकनीकी समस्याओं के कारण या जहाज पर किसी यात्री की मृत्यु के कारण।

वे लोग जो हवाई अड्डे के आगमन अनुभाग के लिए उड़ान भर चुके हैं जहां उन्हें जाना है पुनः दर्ज the सुरक्षा कतार। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है और थकाऊ देरी बढ़ सकती है और यह एयरलाइंस को यात्रियों को उतारने से हतोत्साहित करने के लिए जाना जाता है।

बीसीएएस ने 30 मार्च को नया प्रोटोकॉल जारी किया। बीसीएएस के महानिदेशक जुल क्वार असन ने बताया, "हवाईअड्डों द्वारा अपेक्षित बुनियादी ढांचा स्थापित करने के बाद एसओपी लागू की जाएगी और हमने इसकी समीक्षा की है।" हिन्दू.

कार्यानवयन के लिए अभी तक कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हवाई अड्डों को अपने कुछ बोर्डिंग गेटों पर "रिटर्न बोर्डिंग" के लिए जगह चिह्नित करने की आवश्यकता होगी जहां सीआईएसएफ करमी और एक्स-रे मशीनें होगी खराब यात्रियों की तलाशी लेने और कैंबिन बैगों की स्कैनिंग करने के लिए काम में लिया गया।

को मारने के लिए गोली मारो

के रूप में ऑर्डर करने की संभावना है

आदमी मर जाता है
जंबो हमला

द हिंदू बयरो
पथानामथिट्टा

पथानामथिट्टा के जंगल का किनारा फूट पड़ा
सोमवार तड़के एक जंगली हाथी द्वारा मानव आवास में घुस आए 50 वर्षीय व्यक्ति को कुचलकर मार डालने के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। वन विभाग ने जानवर के लिए "शूट टू किल" आदेश की सिफारिश की है।
<div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>पीड़ित, बीजू कुदिलिल,</div>50, थुलापल्लू के पास पुलिसयानकुनुमुला के रहने वाले थे। घटना रात करीब 1.30 बजे घटी जब वह हाथी को भगाने के लिए अपने पिछबाड़े में गया।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>रिपोर्टरों के अनुसार, बीजू यह सुनकर जाग गया कि हाथी ने उसकी संपत्ति पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और उसे भगाने का प्रयास किया। हालांकि, हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>स्थानीय निवासियों की सूचना पर पम्पा पुलिस स्टेशन और कनामाला वन स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि, गुस्साएं निवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सौंपने से इनकार कर दिया</div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>गॉव में जानवर की मौजूदगी के बारे में पूरव अलर्ट के बावजूद। विभाग ने किया खंडन</div>इन आरोप.</div></div></div> <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>पथानामथिट्टा जिला कलेक्टर एस. प्रेम कृष्णन द्वारा प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद विरोध समाप्त हो गया। इसके बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोट्टायम में स्थानांतरित कर दिया गया।</div></div></div></div>

	
पीड़ित, बीजू कुदिलिल,	
50, थुलापल्लू के पास पुलिसयानकुनुमुला के रहने वाले थे। घटना रात करीब 1.30 बजे घटी जब वह हाथी को भगाने के लिए अपने पिछबाड़े में गया।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>रिपोर्टरों के अनुसार, बीजू यह सुनकर जाग गया कि हाथी ने उसकी संपत्ति पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और उसे भगाने का प्रयास किया। हालांकि, हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>स्थानीय निवासियों की सूचना पर पम्पा पुलिस स्टेशन और कनामाला वन स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि, गुस्साएं निवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सौंपने से इनकार कर दिया</div></div></div></div></div>	

	
पीड़ित, बीजू कुदिलिल,	
50, थुलापल्लू के पास पुलिसयानकुनुमुला के रहने वाले थे। घटना रात करीब 1.30 बजे घटी जब वह हाथी को भगाने के लिए अपने पिछबाड़े में गया।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>रिपोर्टरों के अनुसार, बीजू यह सुनकर जाग गया कि हाथी ने उसकी संपत्ति पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और उसे भगाने का प्रयास किया। हालांकि, हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>स्थानीय निवासियों की सूचना पर पम्पा पुलिस स्टेशन और कनामाला वन स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि, गुस्साएं निवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सौंपने से इनकार कर दिया</div></div></div></div></div>	

	
पीड़ित, बीजू कुदिलिल,	
50, थुलापल्लू के पास पुलिसयानकुनुमुला के रहने वाले थे। घटना रात करीब 1.30 बजे घटी जब वह हाथी को भगाने के लिए अपने पिछबाड़े में गया।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>रिपोर्टरों के अनुसार, बीजू यह सुनकर जाग गया कि हाथी ने उसकी संपत्ति पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और उसे भगाने का प्रयास किया। हालांकि, हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>स्थानीय निवासियों की सूचना पर पम्पा पुलिस स्टेशन और कनामाला वन स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि, गुस्साएं निवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सौंपने से इनकार कर दिया</div></div></div></div></div>	

	
पीड़ित, बीजू कुदिलिल,	
50, थुलापल्लू के पास पुलिसयानकुनुमुला के रहने वाले थे। घटना रात करीब 1.30 बजे घटी जब वह हाथी को भगाने के लिए अपने पिछबाड़े में गया।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>रिपोर्टरों के अनुसार, बीजू यह सुनकर जाग गया कि हाथी ने उसकी संपत्ति पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और उसे भगाने का प्रयास किया। हालांकि, हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>स्थानीय निवासियों की सूचना पर पम्पा पुलिस स्टेशन और कनामाला वन स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि, गुस्साएं निवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सौंपने से इनकार कर दिया</div></div></div></div></div>	

	
पीड़ित, बीजू कुदिलिल,	
50, थुलापल्लू के पास पुलिसयानकुनुमुला के रहने वाले थे। घटना रात करीब 1.30 बजे घटी जब वह हाथी को भगाने के लिए अपने पिछबाड़े में गया।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>रिपोर्टरों के अनुसार, बीजू यह सुनकर जाग गया कि हाथी ने उसकी संपत्ति पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और उसे भगाने का प्रयास किया। हालांकि, हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>स्थानीय निवासियों की सूचना पर पम्पा पुलिस स्टेशन और कनामाला वन स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि, गुस्साएं निवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सौंपने से इनकार कर दिया</div></div></div></div></div>	

कांग्रेस को बुढ़ापा

पूर्व बीआरएस विधायक की बेटी वारंगल सीट से

द हिंदू बयरो
हैदराबाद

कांग्रेस पूर्व बीआरएस विधायक कादियाम श्रीहरि की बेटी कादियाम काव्या को उम्मीदवार बनाएगी, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, जो तेलंगाना के वारंगल (एससी) लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>तेलंगाना पर कांग्रेस चुनाव समिति द्वारा मंजूरी दी गई, जिसने सोमवार को नई दिल्ली में बैठक की और चार लंबित नामों पर चर्चा की।</div></div></div></div>

SC ने शुद्ध उधार सीमा पर केरल सरकार के मुकदमे को वी-जज बेच को भेजा

कोर्ट का कहना है कि केंद्र ने केरल को ₹13,608 करोड़ की 'पर्याप्त राहत' दी है ; इसने सरकार को केरल के लिए शुद्ध उधार सीमा को उठाने या राज्य को तत्काल आधार पर ₹26,226 करोड़ उधार लेने में सक्षम बनाने का निर्देश देने वाला कोई भी न्यायिक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

कृष्णदास राजगोपाल
नई दिल्ली

टीवह सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पुनः संविधान की ओर ले जाया गया-टयूशन बेच ने केरल द्वारा उठाए गए सवाल पर सवाल उठाया कि क्या किसी राज्य को पास केंद्र सरकार और अन्य से उधार लेने की सीमा बढ़ाने का "प्रवर्तनीय अधिकार" है? स्रोत.

अदालत चाहती है कि एक न्यायाधीशों पीठ इस पर फैसला करे-कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें यह भी शामिल है कि क्या "स्केल विकेंद्रीकरण" भारतीय संघवाद का एक पहलू था और क्या राज्यों पर शुद्ध उधार सीमा तय करने वाले केंद्रीय नियम संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन थे। इसने इस मुद्दे को उठाया कि क्या केंद्र द्वारा लागू किए गए वित्तीय प्रतिबंधों ने केरल के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है

	
तुलना साथ अन्य राज्य.	
जस्टिस सुर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ भी	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>संविधान पीठ से यह जांच करने की मांग की गई कि क्या केंद्र के उधार प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक को "सार्वजनिक ऋण प्रबंधन" के रूप में सौपी गई भूमिका के अनुरूप थे।</div></div></div></div>	

	
एर।" अंत में, दो-न्यायाधीश बेच ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र के लिए राज्यों के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>पुनः प्रभाव देने के लिए वित्त आयोग की सराहना.</div>यह संदर्भ केरल के नेतृत्व में आरोप लगाने वाले एक मूल मुकदमे के आधार पर आया था</div></div></div>	



जिसके कारण केंद्र सरकार मनमाने ढंग से अपनी उधार सीमा पर रोक लगा रही है राज्य इससे बच रहा है वित्तीय आपातकाल के कगार पर, वेतन, पेशन और अपनी अन्य आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ।

हालाँकि, पीठ को अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने की केरल की क्षमता पर संदेह था। इसने केंद्र सरकार को केरल के लिए शुद्ध उधार सीमा को उठाने या राज्य को तत्काल आधार पर ₹26,226 करोड़ उधार लेने में सक्षम बनाने का निर्देश देने वाला कोई भी न्यायिक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। "यदि राज्य ने अपने स्वयं के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण अनिवार्य रूप से वित्तीय कठिनाई पैदा की है, तो ऐसी कठिनाई को एक अप्रूपीय क्षति नहीं माना जा सकता है जिसके लिए संघ के खिलाफ अंतरिम राहत की आवश्यकता होगी ... यह

एक बुरी मिसाल कायम हो सकती है ऐसे कानून में जो राज्यों को स्केल नीतियों से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगा और फिर भी सफलतापूर्वक अतिरिक्त उधार का दावा करेगा-आईएनजी, "अदालत ने कहा। "खंडपीठ ने टिप्पणी की केंद्र ने पहले ही राज्य को संकट से निपटने के लिए ₹13,608 करोड़ की "पर्याप्त राहत" की अनुमति दे दी है।

 आदेश था
<i>विज्जायन अंतरिम</i>
मुकदमे में उठाए गए कानून की परकृति और सवालों की जांच वी-जज बेच द्वारा की जाएगी

अनुच्छेद 293 के खंड (3) की व्याख्या करनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट

	
तत्काल संकट. अदालत ने कहा कि "सुविधा का संतुलन" केंद्र के पक्ष में रहे अभी के लिए क्योंकि उसने पहले ही राज्य को अतिरिक्त राशि दे दी थी।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>हालाँकि, अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र के आचरण पर अपनी अस्वीकृति को भी उजागर किया जब उसने वित्तीय मदद के बदले में राज्य पर अपना मुकदमा वापस लेने का दबाव डाला था।</div></div></div></div>	

कोर्ट ने यह आदेश दिया था*विज्जायन अंतरिम*परकृति में और मुकदमे में उठाए गए कानून के बड़े सवालों की जांच वेज जज बेच द्वारा की जाएगी, जिसे बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश गठित करेंगे।

	
डिवीजन बेच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 293 के संबंध में कानून में शून्यता है।	

केरल ने संपर्क किया था शीघ्र अदालत यह तर्क दे रही है राज्य की उधार लेने की शक्तियों पर केंद्र का बंधन संघवाद पर हमला था और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विघटन के लिए उत्तुर्प्रेरक था। राज्य ने तर्क दिया था कि उधार लेने की सीमा राज्यों द्वारा तय की जानी चाहिए।

एक सकारात्मक कदम जिससे दूसरों को फायदा होगा राज्य भी: केरल

द हिंदू बयरो
तिरुवनंतपुरम

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने सोमवार को इसे "सकारात्मक" बताया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी उधार सीमा पर राज्य सरकार के मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेजे।

श्री बालगोपाल ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राज्य के रुख की पुष्टि के रूप में चित्रित किया। "यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने माना है कि केरल के नेतृत्व वाला मुकदमा इतना गंभीर है कि इसकी जांच की जा सकती है। संविधान द्वारा खनन-अल बेच, "श्री बालगोपाल ने कोल्लम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। श्री बालगोपाल ने कहा कि अदालत का फैसला केंद्र-राज्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है, खासकर संघवाद और शासन से संबंधित मामलों में। इससे पता चलता है कि तर्क में वास्तव में दम है-

	
राज्य द्वारा की गई टिप्पणियाँ संघवाद और स्केल मामलों के संबंध में सरकार।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>"यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अदालत ने इसका उल्लेख किया है को the संवैधानिक बेच ने एक मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसे केंद्र अपने नेतृत्व में सरसरी तौर पर खारिज करना चाहता था, "उन्होंने कहा।</div>अदालत में गिरावट पर</div></div></div>	

SC ने हरियाणा सरकार की याचिका खारिज की किसान की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ याचिका

द हिंदू बयरो	
नई दिल्ली	
	
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब-हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान 22 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत की जांच के लिए न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सीमा।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>किसानों के विरोध प्रदर्शन को सीमाओं पर हरियाणा पुलिस के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।</div></div></div></div>	

	
किसानों का विरोध प्रदर्शन सीमा पर हरियाणा पुलिस के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जो प्रदर्शनकारी थे	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>फरवरी में दिल्ली की ओर मार्च करने वाले लोगों को सीमाओं पर रोक दिया गया। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी.</div>सामने आ रहा है ए</div></div></div> <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>जस्टिस सुर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेच ने हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कमेटी का गठन</div></div></div></div>	

	
एक सेवानिवृत्त पंजाब के नेतृत्व में और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य पुलिस के लिए "निराशाजनक" थे।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>श्री मेहता ने कहा कि हरियाणा पुलिस किसान शुभकरण सिंह की मौत की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम है।</div></div></div></div>	

	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>"यह हतोत्साहित करेगा हरियाणा पुलिस. पुलिस बल पर भरोसा क्यों नहीं? जाँच करना? सड़सठ घातक हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों का सामना करते हुए पुलिस अधिकारी घायल हो गए...</div>जांच अब कॉम पर-</div></div></div> <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति राज्य पुलिस के मनोबल को प्रभावित करेगी... कल, एक पुलिस अधिकारी जवाब देने में संकोच करेगा," श्री</div></div></div></div>	

पिनाराई ने कांग्रेस पर हमला किया, कहा कि सबसे पहले

उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग की

द हिंदू बयरो	
तिरुवनंतपुरम	
	
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की "लालसा" रखने और पुलिस शिकायत पर खेद व्यक्त नहीं करने के लिए कांग्रेस पर तीखा हमला किया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए जांच करने और AAP को जेल में डालने का दरवाजा खोल दिया। नेता।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सोमवार को कोझिकोड में पत्रकारों से बात करते हुए, श्री विजयन ने, हालांकि, देर से श्री केजरीवाल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कांग्रेस की सराहना की और असहमति को शांत करने, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने, विपक्षी दलों के अभियान को बाधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक एजेंसियों को तोड़ने की निंदा की। और इंजीनियर दलबदल कर संघ परिवार में चले गए।</div></div></div></div>	

	
केंद्र सरकार की ओर से चेतावनी और धमकियाँ। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व कांग्रेस नेता अशोक चौहान रोए और सवीकार किया कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के डर ने उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया था।"	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>श्री विजयन ने कहा कि राजनीति कोई कुरसी पर बैठने का काम नहीं है और नेताओं में सत्तावाद और कानून-व्यवस्था मशीनरी के दुरुपयोग का सामना करने और उसे हराने का साहस और नैतिक साहस होना चाहिए। उन्होंने कहा-</div></div></div></div>	

	
कांग्रेस नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही थी और वे खतरे का जरा सा भी संकेत मिलते ही पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर राष्ट्रीय हित के प्रति अंधी रहती है और राजनीतिक लाभ की बलिवेदी पर इसे बलिदान कर देती है। राहुल गांधी समेत इसके नेताओं ने नागरिकता लागू करने के खिलाफ कुछ नहीं बोला है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>(संशोधन) अधिनियम. वे करोड़ों भारतीयों पर आए संकट को नकार दिया है-</div></div></div></div>	

एपी की 'दिविसीमा गांधी' जेएसपी में शामिल हुईं

आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मंडली बुद्ध प्रसाद सोमवार को काकीनाडा में जन सेना पार्टी में शामिल हो गए। गांधीवादी मंडली वेकट कृष्ण राव के पुत्र श्री प्रसाद 'दिविसीमा गांधी' के नाम से लोकप्रिय हैं।

	
आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मंडली बुद्ध प्रसाद सोमवार को काकीनाडा में जन सेना पार्टी में शामिल हो गए। गांधीवादी मंडली वेकट कृष्ण राव के पुत्र श्री प्रसाद 'दिविसीमा गांधी' के नाम से लोकप्रिय हैं।	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>राज्य से सीटें पराप्त करना। डॉ. काव्या, जिनहें वारंगल से चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस द्वारा नामित किया गया था रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए।</div>हालांकि कांग्रेस सूची अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, सूत्रों ने कहा कि हैदराबाद शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह को हैदराबाद में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा. ए पूर्वीण रेड्डी करीमनगर सीट से उम्मीदवार होंगे.</div></div></div>	

मूलपाठ & प्रसंग

0

समाचार संख्या में

इस वर्ष एशिया के लिए विश्व बैंक का विकास पूर्वानुमान

भारत के पनबिजली उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है

उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान

कोयला क्षेत्र के उत्पादन में साल-दर-साल वृद्धि फरवरी 2024

फिलिस्तीनी तक मारे गए सोमवार से गाजा में 7 अक्टूबर

4.50इंच प्रतिशत की अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ऋण, व्यापार बाधाएं और नीतिगत अनिश्चितताएं क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता को सुस्त कर देती हैं। एपी

16.30इंच प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की गिरावट नतीजतन नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में गिरावट के साथ मेल खाती है क्योंकि प्रधान मंत्री ने सौर और पवन श्रमता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई थी। रॉयटर्स

उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस, मौसम कृषि में भारी वृद्धि की भविष्यवाणी की है। हालांकि चूंकि अधिकांश गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है, इससे इसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीटीआई

प्रतिशत। के अनुसार के सूचकांक में, कोयला उद्योग ने पिछले आठ महीनों में निरंतर दोहरे अंक की वृद्धि का प्रदर्शन किया है। पीटीआई

32,845 युद्ध 11.6 इंच अधिकांश लोगों

को विस्थापित कर दिया और इसके एक तिहाई निवासियों को अकाल के कमार पर पहुंचा दिया। एपी

Big Data from WhatsApp

हमारे पर का पालन करें

facebook.com/thehindu

twitter.com/the_hindu

instagram.com/the_hindu

लद्दाख का विरोध; न्याय की भूख

केंद्र के साथ बातचीत में लैब-केडीए प्रतिनिधियों की प्रमुख मांगें क्या हैं? लद्दाख में स्थानीय संसाधनों, विशेषकर जल और भूमि पर मुख्य दबाव क्या हैं? पर्यटन विकास लद्दाख में संसाधन तनाव में कैसे योगदान देता है?

व्याख्याता

Kavita Upadhyay

अब तक कहानी:

6 मार्च को लेह नामक कस्बे में लद्दाख में लगभग 3.2 लाख लोग एक विरोध में शामिल हुए। लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद् और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने 21 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की, जिसे उन्होंने "जलवायु उपवास" कहा। यह हड़ताल उन हजारों लद्दाख निवासियों के समर्थन में थी जो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और इसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे भूमि और पानी जैसे संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन के संबंध में निर्णय ले सकें, जो वे वर्तमान में कर रहे हैं। नहीं कर सकते। श्री वांगचुक ने 26 मार्च को अपनी भूख हड़ताल बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से "यह साबित करने का आग्रह किया कि वे राजनेता हैं"। लेह में महिलाओं का चरना कलहाल जारी है, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो युवाओं, शिक्षकों और बुजुर्गों ने कहा है कि वे भी चरनाबद्ध तरीके से भूख हड़ताल में शामिल होंगे।

केंद्रशासित प्रदेशों के गठन ने लद्दाख की निर्णय लेने की शक्तियों को कैसे प्रभावित किया है?

अगस्त 2019 में, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसने लोगों के भूमि और नौकरियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत, लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बना गया।

राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समूहों के समूह लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के समन्वयक जितेंद्र पलजोर ने कहा, "हमारे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एक उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो लद्दाख का निवासी नहीं है, और फिर भी हमारे भविष्य के लिए निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया जाता है।", और बौद्ध-बहुल लेह जिले के छात्र संगठन।

कई नौकरशाह प्रमुख पदों पर, मुस्लिम बहुल कारगिल जिले के कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के कोर कमेटी सदस्य सज्जद कारगिल ने कहा कि क्षेत्र के भविष्य के लिए निर्णय लेने वाले भी लद्दाख के निवासी नहीं थे।

लेह के समान, केडीए कारगिल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और छात्र संगठनों का एक समूह है।

श्री कारगिली ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के बाद लेह और कारगिल में मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) शक्तिहीन हो गई हैं।

लद्दाख औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2023 का मसौदा एक उदाहरण है। जबकि एलएएचडीसी के पास भूमि उपयोग और उसके प्रबंधन पर निर्णय लेने की शक्तियां हैं, मसौदा नीति, जिसे लद्दाख में निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन्हें भूमि आवंटन और पट्टे से संबंधित निर्णय लेने से संबंधित किसी भी शक्ति से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

श्री पलजोर ने कहा कि लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण चीन के साथ-साथ क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रहे उद्योगों के कारण अपनी चरगाहदारी भूमि खो रहे हैं, और फिर भी प्रभावित निवासियों के पास अपनी भूमि से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

एलएबी और केडीए ने तर्क दिया है कि छठी अनुसूची इन मुद्दों से निपटने में मदद कर सकती है क्योंकि यह क्षेत्रीय और जिला परिषदों की स्थापना को सक्षम बनाती है, जिनके पास चरगाहदारी, कृषि, आवासीय उद्देश्यों और अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। निवासियों के हित।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मानना ​​है कि लद्दाख की 2.74 लाख (2011 की जनगणना) से अधिक की 97% से अधिक आबादी आदिवासी है।



कार्वाई का आह्वान: सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल विरोध के दौरान एक बच्चा एक तख्ती लिए हुए है। एएनआई

2019 में सिफारिश की गई कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाया जाए।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भी शामिल है 2019 के लोकसभा और 2020 के एलएएचडीसी चुनावों से पहले इसके घोषणापत्र में, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाने का वादा किया गया था। यह अधूरा रहता है।

लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार में भाजपा को मनाने के प्रयास में, लैब-केडीए प्रतिनिधियों ने 2020 से इस वर्ष 4 मार्च के बीच कम से कम 10 मौकों पर विभिन्न मंत्रियों के साथ चर्चा की है। इनमें से कुछ वार्ताएं, जिनमें सबसे हालिया 4 मार्च की बातचीत भी शामिल है, श्रीमान के साथ हुई हैं।

शाह.

श्री कारगिली, जो केंद्र के साथ वार्ता में भाग ले रहे हैं, ने कहा कि 2021 से लैब-केडीए की मांगों में छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय शामिल हैं, या तो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा या इसे विभाजिका के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना, लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग।, और कारगिल और लेह के लिए अलग संसदीय सीटें। केंद्र ने अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं किया है।

श्री कारगिली ने कहा, "मौजूदा भूख हड़ताल केंद्र के साथ कई असफल वार्ताओं का परिणाम है।"

स्थानीय संसाधनों पर क्या दबाव है?

पर्यटन मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, लद्दाख में घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या देबी जा रही है। 2022 में, 5 लाख से अधिक घरेलू पर्यटकों ने इस क्षेत्र का दौरा किया। अकेले लेह में, जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है, जहां 2007 में केवल आधे लाख से अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटक आए थे, 2018 तक यह संख्या बढ़कर 3.2 लाख हो गई थी। 2019 में प्रकाशित एक शोध लेख में कहा गया है कि शहर में निर्मित क्षेत्र 1969 में 36 हेक्टेयर से बढ़कर 2017 में 196 हेक्टेयर हो गया है।

तेजी से हो रहे शहरीकरण और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण लद्दाख में संसाधनों, विशेषकर पानी पर काफी दबाव पड़ रहा है।

लेह में पानी से संबंधित मुद्दों पर एक रिपोर्ट

2019 में ड्रेमन ओबस्वीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, साउथ एशिया (BORD-SA) और लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप द्वारा प्रकाशित गणना के अनुसार, लेह में, एक पर्यटक गर्मियों में एक दिन में लगभग 100 लीटर और सर्दियों में 60 लीटर पानी का उपयोग करता था, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति पानी का उपयोग करता था। गर्मियों में प्रतिदिन लगभग 75 लीटर और सर्दियों में 50 लीटर। गरीबों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को प्रति व्यक्ति प्रति दिन केवल 25-35 लीटर पानी ही उपलब्ध था। रिपोर्ट में पाया गया कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भूमिगत जल पर निर्भरता, जो अक्सर दूषित होता है, बढ़ गई है।

बोर्ड-एसए के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक और रिपोर्ट के सह-लेखक स्टैनज़िन स्लेफेल ने कहा कि मुदा उपलब्धता के बजाय जल प्रबंधन का था।

ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डेलेक्स नामग्याल ने कहा कि संसाधनों पर दबाव हर साल मई और जुलाई के बीच चरम पर्यटन सीजन के दौरान विशेष रूप से अधिक होता है, जब लगभग 70% पर्यटक घुटी का दौरा करते हैं।

हालांकि, श्री नामग्याल चिंतित थे पर्यटन के खिलाफ संभावित कथा के बारे में चल रही भूख हड़ताल को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि पर्यटक लद्दाख आए क्योंकि यह हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम टिकाऊ पर्यटन चाहते हैं और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।"

जलवायु परिवर्तन से क्षेत्र को किस प्रकार खतरा है?

पिछले दो दशकों में, लद्दाख कई अपवादों, भूस्खलन और जलवायु वर्षा की घटनाओं से प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए, अगस्त 2010 में, लद्दाख के कई हिस्से, विशेषकर लेह, राख की चपेट में आ गए थे।

जलप्रलय में करीब 255 लोगों की मौत हो गई, अगस्त 2014 में, एक हिमनद झील के टूटने से हुए हिमनद झील विस्फोट (जीएलओएफ) ने ग्या गांव में घरों और पुतलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

अभी हाल ही में, अगस्त 2021 में, कंबक गांव के पास एक GLOF ने भी सड़कों और एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया।

2020 में प्रकाशित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है

सार

लेह में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 2019 में जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद, निर्णय लेने में स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए लद्दाख को राज्य का दर्जा और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करती है।

तेजी से शहरीकरण और पर्यटन विकास लद्दाख के संसाधनों, विशेष रूप से पानी पर दबाव डाल रहे हैं, जिसे खिरता और समान पुद्घ पर चिंताएं पैदा हो रही हैं।

पर्यटन के कारण बढ़ी भूमिगत जल पर निर्भरता को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उजागर किया गया है।

लद्दाख को जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ), पर्माफ्रॉस्ट गिरावट और बढ़ते तापमान शामिल हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और पर्यटन लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं।

कि लद्दाख में 192 हिमनदी झीलें हैं। कई शोध लेखों में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान के कारण हिमालय में हिमनद झीलों की संख्या और आकार बढ़ रहे हैं और ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं।

इस प्रवृत्ति से खतरा बढ़ गया है

कश्मीर विश्वविद्यालय के ग्लेशियोलॉजिस्ट इरफान रशीद, जो ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में स्थित घुटी में शोध करते हैं, ने कहा कि लद्दाख में संभावित जीएलओएफ, विशेष रूप से ग्लेशियरों के किनारे बनी प्रोग्लेशियल झीलों से।

डॉ. ने कहा, "बड़े हुए तापमान के परिणामस्वरूप पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण हो रहा है और लद्दाख में कीचड़ पैदा हो रहा है।"

रशीद ने जोड़ा।

लेह स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सोमन लोटस के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के रुझान से क्षेत्र के न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि देखी जा रही है।

जबकि 2011 में सबसे कम न्यूनतम तापमान शून्य से 23.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था, 2023, 2022 और 2021 में यह क्रमशः शून्य से 16.8 डिग्री सेल्सियस, शून्य से 18 डिग्री सेल्सियस और शून्य से 16 डिग्री सेल्सियस नीचे था, श्री लोटस ने कहा।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ते चुनौतियों के बावजूद, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों की नजर लद्दाख पर है, और पर्यटन से संबंधित गतिविधियां बढ़ रही हैं। महत्वपूर्ण पर्यटक प्रवाह के साथ, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक (जैसे कार्बन कार्बन) बर्फ और बर्फ पर जम जाएंगे और पिघलने में तेजी आएंगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर के मोहम्मद फारूक आजम, जिन्होंने लद्दाख में ग्लेशियो-हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन किया है, ने कहा कि खनन गतिविधियों से ढलान की अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे वे भूस्खलन-प्रणण हो सकते हैं। खनन से निकलने वाली धूल ग्लेशियरों पर जम जाएगी जिससे उनके पिघलने की गति भी तेज हो सकती है।

कृषि उपाध्याय एक स्वतंत्र पत्रकार और शोधकर्ता हैं जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण प्रशासन के मुद्दों पर लिखती हैं

10 हिन्दू समाचार

मंगलवार, 2 अप्रैल 2024

दिल्ली

पेज वन से

केंद्र, कांग्रेस विवाद कच्चाथीवू मुद्दे पर

श्री जयशंकर ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कहना गलत है कि कच्चातिवू का "छोड़ना" एक "पुराना मुद्दा" था जिसे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया जा रहा था। श्री जयशंकर ने कहा, "यह संसद में बार-बार उठाया गया है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार पत्राचार का मामला रहा है।" उन्होंने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री (एमके स्टालिन) को कम से कम 21 दिनों तक जवाब दिया है। समय"।

उन्होंने आगे कहा, "हमें कोई समाधान निकालना होगा। हमें श्रीलंकाई सरकार के साथ बैठकर इस मुद्दे पर काम करना होगा।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कच्चातिवू द्वीप के प्रति उदासीनता दिखाई और इसके विपरीत कानूनी विचारों के बावजूद भारतीय शेरमेन के अधिकारों को छोड़ दिया।

समझौते को खिलाफ सार्वजनिक रुख को लेकर दूरम्क पर हमला करते हुए, श्री जयशंकर ने कहा कि इसके नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि को समझौते के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, जो पहली बार भारत और श्रीलंका के बीच 1974 में हुआ था।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस और दूरम्क ने इस मुद्दे को संसद में इस तरह उठाया जैसे कि वे इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, जबकि वे वही दल है जिन्होंने ऐसा किया।" यह स्थिति।

कांग्रेस ने क्विपक्षी नेताओं ने मंत्रालय की 2015 की आरटीआई प्रतिक्रिया का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पिछले समझौते में "भारत से संबंधित क्षेत्र का अधिग्रहण या त्याग शामिल नहीं था"।

"जैसे को तैसा पुरानी बात है। टवीट के बदले टवीट नया हथियार है. क्या विदेश मंत्री श्री जयशंकर कृपया दिनांक 27-1-2015 के आरटीआई उत्तर का संदर्भ लेंगे...उत्तर ने उन परिस्थितियों को उचित ठहराया जिनके तहत भारत ने स्वीकार किया कि एक छोटा द्वीप श्रीलंका का है," प्रूव वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने एक में कहा एक्स पर पोस्ट करें

प्रूव केंद्रीय मंत्री आनंद शरमा ने कहा कि भारत के रणनीतिक हितों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को चुनावी विमर्श में नहीं खीना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि क्या श्री जयशंकर विदेश मंत्रालय द्वारा दिए हुए आ जवाब को असवीकार कर रहे हैं जो तब प्रसारित हुआ जब वही डॉ. जयशंकर विदेश सचिव थे।

कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है कि सकल प्राप्ति कर योग्य थी।

"सकल प्राप्ति कभी भी कर योग्य नहीं होती है। केवल कुल आय ही कर योग्य है। हम एक राजनीतिक दल हैं, कोई सभ्यक संगठन नहीं," श्री सिंघवी ने तर्क दिया। उन्होंने मुद्दा उभारा कि आयकर अधिनियम की धारा 13ए राजनीतिक दलों को कड़ा छूट प्रदान करती है।

श्री मेहता ने कहा कि कुल ₹3,500 करोड़ से अधिक पिछले सात वर्षों का "ब्लॉक मूल्यांकन" था। इसमें कुर्की के जरिए पार्टी से वसूले गए ₹135 करोड़ शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि विभाग ने चुनाव की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए

जबरदस्ती के कदमों से बचने के लिए सवेच्छा" दी है। उन्होंने यह बताना सुनिश्चित किया कि इस तथ्य के बावजूद कांग्रेस को छूट दी गई थी कि मार्च 2024 की ₹3,500 करोड़ से अधिक की कर मांगें शीर्ष अदालत में लंबित अपीलों से सख्तों से संबंधित नहीं थी।

मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि "इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं, उन पर अभी फैसला सुनाया जाना बाकी है, लेकिन सिलिसिटर-जनरल द्वारा एक बयान दिया गया है कि आयकर विभाग ऐसा नहीं करना चाहता है।" मामला को इनना रफा-दफा करे कि लगभग ₹3,500 करोड़ की मांग के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।"

अदालत ने विभाग के बयान को आगे दर्ज किया कि कांग्रेस को "किसी भी जबरदस्ती कदम के बारे में आशंका" रखने की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया था कि लोकसभा चुनाव की पूरव संध्या पर जारी किए गए कर नोटिसों से स्थिति सत्तापूढ़ भाजपा के पक्ष में झुक जाएगी।

लोगों को थका देने वाले इंतज़ार से बचाने के लिए नया नियम

वैकल्पिक रूप से, यात्रियों को पहले से मौजूद सुरक्षा जांच क्षेत्र में ले जाया जा सकता है जिसके लिए एक रोगाणुहीन मार्ग बनाना होगा। प्रोटोकॉल के अनुसार एयरलाइंस नए बोर्डिंग कार्ड भी प्रिंट कर सकती है।

देरी के दौरान, एक एयरलाइन यह आकलन करेगी कि वापसी बोर्डिंग के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता है या नहीं। इसके बाद उसे मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) या बीसीएसके के एक अधिकारी से परामर्श लेना होगा जो अनुरोध की जांच करेगा और उसे मंजूरी देगा।

यदि कोई एयरलाइन इस तरह के मार्ग के लिए अनुरोध करने और अनुचित देरी के बावजूद निर्धारित एसओपी का पालन करने में विफल रहती है, तो बीसीएसके और सीएसओ भी इसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

जनवरी में, जब देश के कई हिस्सों में कई वर्षों में सबसे खराब कोहरा देखा गया, तो यात्रियों के विमान के अंदर तीन से 12 घंटे तक फंसे रहने के कई मामलों सामने आए। 14 जनवरी को, दिल्ली-गोवा फ्लाइट में एक यात्री ने पायलट की पिटाई भी कर दी, क्योंकि उन्हें लगभग तीन घंटे तक विमान में ही रखा गया था और फ्लाइट में आठ घंटे से ज्यादा की देरी हुई थी। गोवा से उसी विमान की वापसी यात्रा में 12 घंटों की देरी हुई और एयरलाइन को ईंधन भरने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद यात्रियों ने विमान से उतरने के बाद ट्रम्पेक क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एयरलाइन को ₹1.2 करोड़ का नुकसान हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर ₹90 लाख।

उसी दिन, दिल्ली से वैक्चर जा रहे एयर इंडिया के विमान से यात्रा करने वाले यात्री सुबह 4:30 बजे से दोहरा 1:30 बजे तक एक स्थिर विमान के अंदर फंसे रहे।

सीएसओ **वाइक**

हिन्दू समाचार

पूर्व राजनयिकों ने सरकार को चेताया कच्चातिवू पर

श्रीलंका के पूर्व दूतों का कहना है कि पिछले एक दशक में विदेश मंत्रालय की स्थिति पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए रुख के अनुरूप रही है। ; उनका कहना है कि इस मुद्दे पर स्थिति में कोई भी बदलाव पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है और क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है

समाचार विश्लेषण	
सुहासिनी हैदर नई दिल्ली	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>सरकार द्वारा फिर से विचार करने का कोई कदम नहीं 1974 भारत-श्री लंका पर सहमति कच्चातिवू द्वीप क्षेत्र में भारत के संबंधों पर व्यापक राजनयिक प्रभाव डाल सकता है और अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं पर सवाल उठा सकता है।</div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>पूर्व राजनयिक.</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>हाहरी ए परसारित होता है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>एस जयशंकर का कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>चौंहे</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>मंंत्री</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कच्चातीवू द्वीप को "छोड़ने" और स्थिति के लिए "समाधान" खोजने पर सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों ने मंत्रालय की सैचिति पिछले एक दशक में क्विपक्षीय उतारू है</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियों और में उल्लिखित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया-</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>आगाह</div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>अधिकार भी पूछताछ की</div></div></div></div>	

मंगलवार, 2 अप्रैल 2024
दिल्ली



पपू यादव से घटने तक पूर्णिया सीट

अपनी जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) का कांग्रेस में विलय करने वाले बिहार के नेता पपू यादव ने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वह 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

बिहार में, इंडिया बलॉक ने एक समझौता किया है जिसमें राजद 26 सीटों पर, कांग्रेस नौ और वाम दल पांच सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया राजद के खाते में चली गयी है।

हालाँकि, इस सीट को लेकर अभी भी खींचतान जारी है, भले ही राजद परमुख लालू प्रसाद ने रूपायी विधायक बीमा भारती को हरी झंडी दे दी हो।

सीट पर चुनाव लड़े. श्री पपू पूर्णिया से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एकस पर एक संदेश पोस्ट करते हुए कहा, "देश भर में फले पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र के मेरे मित्रों और मेरे नामांकन में भाग लेने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए, मेरे नामांकन दाखिल करने की तारीख 2 अप्रैल के बजाय 2 अप्रैल तक की गई है।" नामांकन 4 अप्रैल है।"



पपू यादव आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे
गुरुवार/फाइल फोटो

सप्ताह बाद रालोद एनडीए में शामिल सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया

राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने...

अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। श्री सिद्दीकी का यह कदम रालोद के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के कुछ सप्ताह बाद आया है। "कल मैंने राष्ट्रीय लोक की सदस्यता से अपना त्यागपत्र भेज दिया है

दल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह को. आज जब भारत का संविधान और लोकतांत्रिक संरचनाएं खतरे में हैं तो चुप रहना पाप है... लेकिन भारी मन से मैं खुद को आरएलडी से दूर करने को मजबूर हूँ, भारत की एकता,

अखंडता, विकास और भाईचारा सभी को प्रिय है। इसे बचाना परत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और कर्तव्य है।" उन्होंने कहा कि रालोद के राजग का हिस्सा बनने से उन्हें निराशा हुई है

परिस्थिति।



वहाँ नहीं चाहिए का कोई भी अर्थ हो ओवरकॉन् डेस... दोनों युद्ध और चुनाव पूरी सावधानी और पूरी ताकत से लड़ना चाहिए

योगी आदिन्याथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

बीजेडी सांसद और अभिनेता मोहंती बीजेपी में शामिल हो गए

अनुभव मोहंती, केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से बीजू जनता दल के निवर्तमान सांसद और उडिया सिनेमा के एक परमुख अभिनेता सोमवार को चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। श्री मोहंती ने 2019 का लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा था

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को हराया.



एकमात्र कारक इस पोल में है मोदी. हर कोई उन्हें दोबारा पीएम बनाना चाहता है. सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो भी नतीजा वही होगा

हिमत बिसुवा सरमा
अरुण के मुख्यमंत्री

चुनाव आयोग की निंदा घोष, श्रीनेत टिप्पणियों पर

द हिंदू बयरो
नई दिल्ली

राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का चुनाव सुनिश्चित करना

आयोग ने सोमवार को कहा कि वह आश्वस्त है कि दोनों नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ "निम्न स्तर के दृष्टिकोण हमले" किए और इस तरह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

दोनों को जारी अलग-अलग नोटिस में कहा गया है कि नेताओं के चुनाव संबंधी संचार पर अब से विशेष और अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी।

नोटिस की एक प्रति संबंधित पार्टी परमूखों को भी भेजी गई, जिसमें उनसे सार्वजनिक क्षेत्र में संचार करते समय सावधानी बरतने के लिए अपने पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा गया।

"आप कृपया चुनाव परचार और सार्वजनिक क्षेत्र में बातचीत में शामिल सभी पार्टी पदाधिकारियों को विशेष सलाह जारी कर सकते हैं कि वे मौजूदा मामले में इस तरह का उल्लंघन न करें, इसके अलावा एमसीसी का अक्षरशः पालन करें ताकि एक शरुंखला शुरू न हो। इसी तरह की टिप्पणियों की प्रतिक्रिया से चुनाव अभियान खराब हो रहा है," यह कहा।

'हे गहन टिप्पणियाँ'

चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते श्री घोष और सुश्री श्रीनेत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिनेता और भाजपा के खिलाफ उमता "गंभीर", "अपमानजनक" और "अशोभनीय" टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा था।

कर्मशः उम्मीदवार कंगना रनौत।

चुनाव आयोग ने कहा था कि उनकी टिप्पणियाँ "अशोभनीय और खराब" थी और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन थी। एमसीसी 16 मार्च से लागू है जब लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

सुश्री श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई भाजपा की एक शिकायत के बाद की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एकस पर "अपमानजनक टिप्पणियों" के साथ सुश्री रनौत की एक तस्वीर पोस्ट की थी। बंगाल के भाजपा नेता श्री घोष को नोटिस, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद जारी किया गया था।

नई टोल दरें लागू होंगी

लोकसभा चुनाव के बाद

प्रेस दरस्ट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

टी चुनाव आयोग (ईसी) ने राज्य के स्वामित्व वाली एनएचआई को नए टोल की गणना के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा है

राजमार्गों पर दरे, जो देश के अधिकांश टोल वाले राजमार्गों खंडों पर 1 अप्रैल से सालाना लागू होंगी हैं, लेकिन कहा गया कि नई उपयोगकर्ता शुल्क लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू होंगी चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक संचार का जवाब देते हुए, चुनाव निकाय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से टोल शुल्क वृद्धि को स्थगित करने के लिए कहा है।

वार्षिक अभ्यास टोल बढ़ोतरी का वार्षिक संशोधन, जो औसतन 5% की सीमा में होने की उम्मीद थी, 1 अप्रैल को अधिकांश टोल वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होना था।

"पावर टेरिफ पर निर्णय के लिए आवश्यक प्रक्रिया राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रखी जा सकती है। हालाँकि, टारी पुरस्कार संबंधित राज्य में मतदान पूरा होने पर ही दिया जाएगा, यानी राज्य में मतदान की तारीख/तारीख के बाद। मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में, यह कहा गया है कि उपयोगकर्ता शुल्क को पावर टेरिफ के संदर्भ में देखा जा सकता है जैसा कि इसमें उल्लिखित है।

आयोग के निर्देश का हवाला ऊपर दिया गया है, "ईसी ने सोमवार को कहा।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, टोल शुल्क में बदलाव उन दलों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो थोक मूल्य सूचकांक-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव से जुड़ी हैं।

द्वीप संधि के लिए गिरती काँटा, रेखा और सीक, लेकिन कोई बड़ी पकड़ नहीं

कच्चाधीवू विवाद को एक बार फिर धूल चटा दी गई है, लेकिन रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र जिसके पास यह द्वीप स्थित है, ने बड़े पैमाने पर द्रमुक या कांग्रेस या इनमें से किसी भी पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों का समर्थन किया है।

फोकस में

टी. रामकृष्णन
चेन्नई

क अचतीवू, बंजर टापू के बारे में 14 समुद्री मील 0 तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम, राजनीतिक बहस का विषय बनने से इनकार करता है, हालांकि भारत और श्रीलंका द्वारा समुद्री सीमा रेखा के सीमांकन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए लगभग 50 साल बीत चुके हैं।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले कच्चाधीवू पर विवाद खड़ा हो गया। एक दैनिक में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एकस (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा: "आंखे खोलने वाली और चौकाने वाली! नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चाधीवू को दे दिया..."

फिर भी, अगर कोई 1977 के बाद से रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डाले तो एक चुनावी मुद्दे के रूप में कच्चाधीवू की उपयोगिता संदिग्ध है। अब तक हुए 12 चुनावों में से केवल दो बार (1998 और 2014) इस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार लौटे। जो द्रविड़ मुनेत्र कडम (डीएमके) और द्वारा समर्थित नहीं थे



राजनीतिक विवाद: कच्चाधीवू तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील दूर एक बंजर टापू है।फाइल फोटो

कांग्रेस, दोनों ही अब अपने विरोधियों के निशाने पर है। 1974 में केंद्र में कांग्रेस और राज्य में डीएमके सत्ता में थी। अन्य सभी अवसरों पर, विजेता या तो द्रमुक या कांग्रेस के थे या उन्हें किसी भी पार्टी का समर्थन प्राप्त था।

2019 में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने निर्वाचन क्षेत्र जीता, जिसमें DMK और कांग्रेस शामिल थे।

प्रगति. अब भी, IUML दोनों पार्टियों के समर्थन से फिर से चुनाव की मांग कर रही है। हालाँकि, ए अनवर राजा, वरिष्ठ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र

कजगम नेता जिन्होंने रामनाथपु का प्रतिनिधित्व किया- 2014-2019 के दौरान राम को लगता है कि यह उनकी पार्टी है जो वर्तमान परिस्थितियों में लाभ के लिए खड़ी रहेगी।

"जब 1974 में यह निर्णय लिया गया कि कच्चाधीवू श्रीलंका, कांग्रेस और डीएमके का हिस्सा था

सत्ताधारी दल थे. इसके अलावा, भाजपा, जो 10 साल से सत्ता में है, ने इसे वापस पाने के लिए कुछ नहीं किया," वह बताते हैं।

वह कहते हैं कि यह उनकी पार्टी की परमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता थी, जिन्होंने इस द्वीप को पुनः प्राप्त करने के लिए "वास्तविक कानूनी लड़ाई" शुरू की थी।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ए. गोपनना ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कच्चाधीवू ने कभी भी कोई चुनावी प्रभाव नहीं डाला है।

एसपी का कहना है कि अपना दल (के) और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन बीजेपी द्वारा जन्मा है

मयंक कुमर
लखनऊ

समाजवादी पार्टी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अपना दल (कमेवादी) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के बीच गठबंधन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा धर्मनिरपेक्ष को विभाजित करने के लिए किया गया है। लोकतांत्रिक समर्थक

राज्य में वोट. समाजवादी पार्टी पीडीए ने कहा (*पिचडा*, दलित और *अल्पसंख्यकों*) समुदाय दृढ़ता से इंडिया बलॉक के पीछे है और जानते हैं कि इस तरह के गठबंधन भाजपा को विजयी बनाने के प्रयास है।

"वे (अपना दल और एआईएमआईएम) भाजपा की स्क्विप्ट पढ़ रहे थे। पीडीए वोटों को विभाजित करके भाजपा की मदद करने के लिए गठबंधन बनाया गया है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक लोग हैं

जागृक हैं और जाल में नहीं फंसेगे। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, मतदाताओं ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है और इस तरह की रणनीति का कोई नतीजा नहीं निकलेगा।



नया गठजोड़: रविवार को लखनऊ में अपना दल (के) नेता पल्लवी पटेल के साथ एआईएमआईएम परमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन की घोषणा की।एनआई

अपना दल (के) और एआईएमआईएम ने 31 मार्च को घोषणा की का गठन पीडीएम नयाय मोरचा

हिन्दू

श्री चौधरी ने कहा कि अपना दल (के) नेता और पार्टी परमुख कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल,

चाहिए का त्याग करे विधानसभा की सदस्यता क्योंकि वह 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा के चुनाव चिन्ह पर जीती थी-

रथु सीट. उन्होंने सवाल किया, "जब वह अलग हो गई है तो फिर भी सपा से विधायक बने रहने का क्या मतलब है।"

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में अपना दल (के) और एआईएमआईएम ने 31 मार्च को पीडीएम नयाय मोरचा के गठन की घोषणा की और इसे नयाय के लिए एक राजनीतिक मोर्चा बताया। *पिचडा*, दलित और

उत्तर प्रदेश में मुसलमान. सीट-बंटवारे का मामला पीडीएम द्वारा डिजाइन की गई पीडीएम पिच के साथ प्रतिध्वनित होता है

एनसी के बुजुर्ग उम्मीदवार अनंतनाग से, समाप्त होता है पीडीपी से गठबंधन की संभावना

पिरजादा आशिक
श्रीनगर

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने सोमवार को वरिष्ठ नेता मियां अलताफ को अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया, जिससे भारत के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने की कांग्रेस की कोशिशें खत्म हो गईं।

कश्मीर घाटी में एनसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सहित बलॉक सदस्य।

"निर्वाचन क्षेत्र से मियां अलताफ से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं होगा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी व्यापक लोकप्रियता है। उन्हें लोगों से पर्याप्त समर्थन मिलेगा, "नेकां उपाध्यक्ष उमर अबदुल्ला ने कहा।

एनसी प्रवक्ता इमरान डार ने कहा कि श्री अलताफ को अध्यक्ष बनाना पार्टी का "सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय" था। हमे उम्मीद है कि मतदाता निर्णायक जनादेश देगे और उन ताकतों को कराया जवाब देगे जम्मू-कश्मीर की पहचान किसने छीनी? ty," श्री डार ने कहा।

नेकां ने दक्षिण कश्मीर सीट से एक उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है

एनसी और पीडीपी के बीच सीट व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस द्वारा कई महीनों से की जा रही कोशिशों का अंत हो गया।

दोनों दल गुफ्कर घोषणा के लिए पीपुल्स अलायंस के मुख्य घटक हैं, जो जम्मू-कश्मीर की अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं, जब पूर्ववर्ती राज्य को अनुच्छेद 370 और 35 ए के तहत विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त था।

पीडीपी ने इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वह घाटी की तीन सीटों में से एक पर उम्मीदवार खड़ा करने पर जोर दे रही है।

पीडीपी की पहली पसंद अनंतनाग-राजौरी थी जहां इसकी परमुख महबूबा मुफ्ती ने अतीत में जीत हासिल की थी और इस सीट को पार्टी अपना गढ़ मानती है। हालाँकि, एनसी बड़े उम्मीदवारों पर आई हुई है

सभी तीन सीटों से, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने 2019 के चुनाव में उन्हें जीत लिया। जम्मू-कश्मीर में पांच लोकसभा सीटें हैं, दो जम्मू क्षेत्र और तीन में कश्मीर। कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने जम्मू क्षेत्र में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

एनसी परवर्त

मेंसंकृषिपूत



भारतीय वायुसेना के विमान कश्मीर में राजमार्ग पर लैंडिंग अभ्यास करेंगे

अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा में सड़क की एक पट्टी का उपयोग सोमवार रात से भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के विमानों द्वारा आपातकालीन लैंडिंग अभ्यास करने के लिए किया जाएगा। सुखोई लड़ाकू विमान और तेजस हल्के लड़ाकू विमान के भाग लेने की संभावना है। यह घाटी में आयोजित होने वाली पहली ऐसी ड्रिल है। भारतीय वायुसेना आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक रनवे के रूप में राजमार्गों का उपयोग करेगी। बिजबेहरा में 3.5 किमी हाईवे पर लैंडिंग कराई जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि सभी नागरिक वाहनों को पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संरक्षण पर जाने के लिए सोमवार को निर्देशित किया गया था। ड्रिल में स्वास्थ्य, पुनर्वास और अन्य विभाग भी भाग लेंगे।

एनपीपीए ने 900 से अधिक दवा फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतों में संशोधन किया

सोमवार से एटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाओं की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निरधारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सुनिदा दवाओं की कीमत में 0.00551% की बढ़ोतरी की अनुमति दी थी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने अब 923 अनुसूचित दवा फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित अधिकतम कीमतों और 65 फॉर्मूलेशन की संशोधित खुदरा कीमतों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। यह रिवीजन एक नियमित अभ्यास का हिस्सा है। 2023 में दवाओं की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी की गई थी। 2019 में, एनपीपीए ने इसका इस्तेमाल किया

कई कंपनियों द्वारा उच्च लागत के कारण उत्पादों को बंद करने के लिए आवेदन करने के बाद 21 आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतों को 50% तक बढ़ाने की आपातकालीन शक्तियां।

SC को नोटिस
EC की याचिका पर
ईवीएम की जांच करें,
वीवीपैट की गिनती

द हिंदू ब्यूरो

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस रिट याचिका पर चुनाव आयोग (ईसी) को नोटिस जारी किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की गिनती को अनिवार्य रूप से क्रॉस-वैरिफाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

वोट वास्तव में दर्ज किये गये सभी वोटों को गिनकर डाला गया- वैरी एबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) परीक्षा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की अगुवाई वाली याचिका, जिसका प्रतिनिधित्व वकील नेहा राठी ने किया, को उसी मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया।

सुश्री राठी ने चुनावों में केवल यादृच्छिक रूप से चयनित वीवीपीएटी परीक्षों के सत्यापन की वर्तमान प्रथा के विपरीत, पूरी गिनती के लिए तर्क दिया।

वीवीपैट पेपर परीक्षों के माध्यम से ईवीएम

याचिका आगे चुनाव आयोग के दिशानिर्देश को चुनौती दी, जिसमें अनुक्रमिक वीवीपीएट सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, यानी एक के बाद एक, जिससे अनुचित देरी हो रही है। याचिका प्रस्तावित प्रत्येक निर्याचन क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक क्रमियों को तैनात करके एक साथ वीवीपीएट सत्यापन। याचिका में दावा किया गया, "इससे वीवीपैट सत्यापन पांच से छह घंटे में किया जा सकेगा।"

मनरेगा की मांग में बढ़ोतरी
इस ओर इशारा करती है
सरकार की विफलता: कांग्रेस

डेटा 'व्यापक बेरोजगारी और स्थिर मजदूरी' की ओर इशारा करता है कांग्रेस का कहना है कि यह बात की जा रही विकास कथा के विपरीत है। नेता

द हिंदू ब्यूरो

नई दिल्ली

अक्षयश पर प्रतिक्रिया-एगाशिप ग्रामीण रोजगार के अनुमानित ऑकड़े-नियोजन गारंटी यह योजना दर्शाती है कि काम की मांग महामारी-पूर्व स्तर से अधिक है और लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि यह नरेन्द्र मोदी सरकार की कई विफलताओं का एक "जीवित स्मारक" है।

आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 305.2 व्यक्ति दिवस (सामान्य पाली में काम करने वाला एक व्यक्ति) उत्पन्न हुए।

जो कि 12 करोड़ प्रति से अधिक है। 2022-23 की तुलना में बेटे दिन और 2019-20 में पहले महामारी वर्ष की तुलना में 40 करोड़ अधिक। कई मायनों में 2022-23 को पहला साल माना जा रहा है देश के बाद वर्ष

महामारी के झटके से बाहर आये और अर्थव्यवस्था को गति पकड़ने में समय लगा।

यहां एक विस्तृत बयान में, श्री रमेश ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना (MGNREGS) थी कांग्रेस सरकार द्वारा सुरक्षा जाल के रूप में डिज़ाइन किया गया



मारना:मनरेगा को कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में डिजाइन किया था।फाइल फोटो

ग्रामीण गरीबों के लिए, "यह डी है-मांड-चालित जिसका अर्थ है रोजगार तभी उत्पन्न होता है जब बेहतर वेतन देने का कोई विकल्प नहीं होता है," श्री रमेश ने कहा।

कांग्रेस जनरल सचिव ने कहा कि डेटा "व्यापक बेरोजगारी और स्थिर मजदूरी" की ओर इशारा करता है। उन्होंने सरकार पर आंखे मूंदने का आरोप लगाया, क्योंकि डेटा सरकार द्वारा प्रचारित "विकास" कथा के विपरीत है। "जो सरकार आज की गंभीर वास्तविकता को सुनने से इनकार करती है वह असफल होगी

इसका मुकाबला करने में," उन्होंने कहा।

पीएम की ही नकल कर रहे हैं कार्यकर्ता का वर्णन करने के लिए उन्होंने 2015 में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, श्री रमेश ने कहा कि पिछले साल मनरेगा के व्यक्ति-दिनों में वृद्धि हुई है वास्तव में एक "जीवित स्मारक" मोदी सरकार की कई विफलताओं के लिए।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के प्रति मोदी सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के बावजूद, उसे महामारी के दौरान और दूरभाग्य से वर्तमान में भी गरीबों के लिए आय सहायता के प्राथमिक स्रोत के रूप में इस योजना पर निर्भर रहना पड़ा।

एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए
उन अपराधों पर जो वास्तव में
देश के लिए खतरा हैं: सीजेआई

द हिंदू ब्यूरो

नई दिल्ली

यह रेखांकित करते हुए कि भारत के केंद्रीय ब्यूरो (सीबीआई) जैसी जांच एजेंसियां पिछले कुछ वर्षों में "बहुत पतली" हो गई है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि उन्हें दक्षता को बढ़ावा देने और अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी लड़ाई चुननी चाहिए। देश की सुरक्षा, आर्थिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है।

न्याय चंद्रचूड़ 20वें डीपी कोहली मेमोरियल पर भाषण देते हुए यह टिप्पणी की भाषण पर "गोद लेना तकनीकी को एडवांस क्रिमिनल जस्टिस", केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्थापना दिवस पर। जमीनी या परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करना, "अनुचित" के उदाहरण उतने कहा।

व्यक्तिगत का षडयंत्र

तलाशी के दौरान उपकरणों पर सीजेआई ने कहा कि वे जांच संबंधी अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन के युग में, कानून और प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर क्रिया से अपराध का बेहतर पता लगाया जा सकता है और आपराधिक न्याय सुधार भी सुनिश्चित किया जा सकता है। "प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को अपनाने में, हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं निष्पक्षता, समानता और जवाबदेही के सिद्धांतों के लिए। इन उपकरणों का जिम्मेदारीपूर्वक और नैतिक रूप से उपयोग करके, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि तकनीकी प्रगति का लाभ सभी तक पहुंचे

समाज के सदस्य, उनकी परवाह किए बिना-व्यक्त करना, "अनुचित" के उदाहरण उतने कहा। (पीटीआई इनपुट के साथ)

लेखक ने राजनीतिक हस्तक्षेप का
हवाला देते हुए साहित्य अकादमी छोड़ी

श्रीप्रणा चकरवर्ती

नई दिल्ली

मलयालम के बाद सोमवार को साहित्य अकादमी में विवाद खड़ा हो गया लेखक सी. राधाकृष्णन ने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए प्रमुख साहित्यिक संस्था की सामान्य परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया

दखल अंदाजी। साहित्य अकादमी सदस्य को संबोधित एक पत्र में सचिव के. श्रीनिवासराव, श्री राधाकृष्णन ने कहा: "मैं इस वर्ष के अकादमी महोत्सव का उद्घाटन भारत सरकार के एक कैबिनेट मंत्री द्वारा किए जाने का कड़ा विरोध करता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका साहित्य में कोई भी ज्ञात प्रमाण नहीं है।"

वह केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अरजुन राम मेघवाल द्वारा "साहित्योत्सव: पत्रों का उत्सव" के 29वें संस्करण का उद्घाटन करने का जिक्र कर रहे थे।



सी. राधाकृष्णन

11 मार्च। इस आयोजन में 170 से अधिक भाषाओं के 1,000 से अधिक लेखकों की भागीदारी देखी गई।

हालांकि अकादमी की स्थापना 1954 में सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर बताया गया है।

अपने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उपन्यासों के लिए जाने जाने वाले लेखक ने आगे कहा: "मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं किसी विशेष राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूँ। मैं संस्कृति प्रशासन के राजनीतिकरण का विरोध करता हूँ

अकादमी के स्वतंत्र कद को खत्म करना।"

साहित्य अकादमी उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि श्री राधाकृष्णन का लिखित इस्तीफा "भ्रामक" था।

एक बयान में अकादमी अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि श्री मेघवाल स्वयं एक लेखक थे। उन्होंने मंत्री के कुछ प्रकाशित कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए कहा, "वह राजस्थानी और हिंदी में प्रागत हैं।" बयान में कहा गया है, "इसके अलावा, उन्होंने राजस्थानी भाषा के विकास के लिए कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी को भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए विभिन्न क्षमताओं में पूर्ण सहयोग दिया।"

श्री। राधाकृष्णन यद्यपि अविचल था। "निश्चित रूप से, जो कोई भी कम से कम एक पत्र लिखता है, वह एक लेखक है," उन्होंने संक्षिप्त उत्तर में कहा।

'पन्नून मामले की जांच
राष्ट्रीय का हिस्सा
सुरक्षा हित'

द हिंदू ब्यूरो

नई दिल्ली

विदेश मंत्री एन जयशंकर ने सोमवार को कहा कि अमेरिका स्थित खालिस्तानी अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साजिश की जांच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हिस्सा है। वह नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

इससे पहले, अमेरिकी राजदूत-समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में एरिक गारसेटी ने अमेरिकी धरती पर पन्नून को मारने की कथित साजिश को "अस्वीकार्य लाल रेखा" बताया था।

श्री जयशंकर ने जवाब में कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसकी हम जांच कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि उस जांच में हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल हैं।"

लू की स्थिति
संभवतः चुनाव के दौरान

सीज़न, आईएमडी ने चेतावनी दी है

द हिंदू ब्यूरो

नई दिल्ली

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को अप्रैल और मई में देश के अधिकांश हिस्सों में "सामान्य से अधिक" लू चलने की चेतावनी दी। ये वो महीने हैं जब देशभर में मतदान होने है।



को एडवाइजरी जारी की गई है चुनाव आयोग और राज्यों को पर्याप्त सावधानी बताने के लिए कहा गया है।

चुनाव आयोग (ईसी) और राज्यों को इस संबंध में सलाह जारी की गई है

पर्याप्त सावधानियां। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, ओडिशा, और आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, जहां अप्रैल और मई के दौरान औसतन एक से तीन दिन लू चलती है, वहां दो से आठ दिन लू चलने की संभावना है। लू वाले दिन तब घंटित होते हैं जब दिन का तापमान-

एक जगह पर टयूस कम से कम है लगातार दो दिनों में सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक, या 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक।

जबकि ये क्षेत्र हैं विशेष रूप से असुरक्षित, सामान्य से उपर स्वभाव-केरल, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे देश में बारिश की संभावना है।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव आयोग और को सलाह जारी की गई है

राज्यों को "सावधानी बरतनी" चाहिए और बुध अधिकारियों या मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों को मौखिक पुनर्रजलीकरण नमक से लेस करना चाहिए, जिन्हें हीटस्ट्रोक का अनुभव हो सकता है।

चुनाव आयोग ने कहा, "निर्वाचकों को खुद को निरजलीकरण से बचाने के लिए गीले तौलिए ले जाने की सलाह दी जाती है और महिला मतदाताओं को गर्म मौसम की स्थिति के दौरान छोटे बच्चों को बूथ पर लाने से बचने की सलाह दी जाती है।"

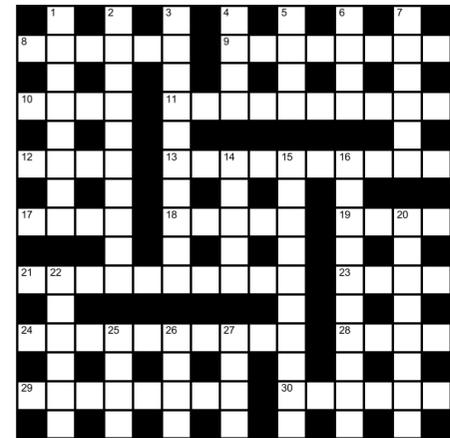
पर एक सलाह में कहा गया 16 मारच। यह देखते हुए कि लोकसभा चुनाव ग्रमियों के महीने में होते हैं, ये चुनाव आयोग द्वारा अपने को भेजी जाने वाली नियमित सलाह है।

ओह सियाल आईएमडी के महानिदेशक एम. महापात्र ने कहा, सामान्य से अधिक गर्मी की उम्मीद का एक कारण अल नीनो का लगातार प्रभाव है। मध्य प्रशांत महासागर के सतही जल के गर्म होने से जुड़ा अल नीनो भारत में बारिश के सूखने से जुड़ा है।

THE CROSSWORD+ 14138

इस पहेली को ऑनलाइन हल करने के लिए, हमारी क्रॉसवर्ड साइट पर जाएं। @ <https://qrgo.page.link/jjptn>

करो को हिल चुकते को



आर-पार

- यह एक से अधिक नियमों में जाता है (6)
- भारतीय आहार का हिस्सा (3-5)
- दोहरी प्रशंसा लौटाता है (4)
- असहनीय सेक्स के कार्य, जिसमें प्रतिरोध शामिल है (10) चुनाव
- जीत अंततः लोगों के पास वापस! (4)
- लहरो द्वारा संदेश कैसे पहुंचाया जाए? (10)

- विशाल भव्य उत्सव का हिस्सा (4)
- मोड़को को डेटा भंडार के लिए व्यवसाय द्वारा बनाए रखा गया (2-3)
- ब्लैक सेंसिटिविटी का समर्थन करे (4)
- मौखिक प्रचार से भी तेज यात्रा? (10) राजा को
- कुलीन समर्थन मिलने की संभावना (4)
- क्या लघु पत्रिका कला संभवतः इसका प्रतीक हो सकती है? संवैधानिक लोकतंत्र (5,5)
- बड़ी, वयस्क, नर काली भेड़ (4)
- वामपंथियों ने जज को हटाया। हटाने से मतदान होता है! (8)
- हल्का घाव (6)

नीचे

- कौलिफोर्निया, कार्टी लॉस एंजिल्स से पेय कंपनी (4,4) किसी व्यक्ति की
- गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले भयानक मतलब पर ध्यान केंद्रित करती है (6,4) कथित तौर पर चैनल के लिए खरीद - छोटे डेरिवेटिव (2-8)
- यह मूल रूप से कृषण, समतलता जैसी पिच स्थितियों को इंगित करता है (4) ठीक है, ठीक है! एक सब्जी के लिए एकड़! (4)
- मूर्खों के लिए कोई सही योजना नहीं (4) देश के
- बच्चे, नियमित रूप से आगे रहना (6)
- बेकार बेवकूफ में भागो (5)
- लोकप्रिय और अधिकांशतः आधुनिक कालजयी युक्ति (10)
- स्वतंत्र बिल नैतिक विश्वास का संदिग्ध स्रोत है व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता (10)
- कुर्प के अंदर कूड़ा इकट्ठा करना (8) नई
- नीली रंग में शक्ति का अभाव है (6)
- कैथोलिक क्रांतिकारी के बारे में ज्ञान का हिस्सा (4) प्रत्येक
- आइडम की एक रसिद है (4)
- प्रबंधित राजा की फाइल (4)

सुडोकू



पिछली पहेली का समाधान

F	E	N	S	H	U	S	I	N
R	E	A	P	E	R	A	N	O
S	I	T	R	A	P	E	R	A
P	R	E	T	I	P	A	S	S
A	D	O	C	H	E	S		
B	A	D	M	O	U	T	H	C
A	T							
S	C	A	R	T				
A	N	T	S	T	E	W	A	R
O	A	T						
T	E	A	R	O	M	S	A	M
A	N	T	H	E	M	R	A	N

कल के सुडोकू का समाधान

3	4	1	6	9	7	5	2	8
6	5	7	2	1	8	3	9	4
2	8	9	4	5	3	1	6	7
9	3	5	1	8	2	4	7	6
1	7	6	9	3	4	2	8	5
4	2	8	5	7	6	9	3	1
7	9	2	8	4	5	6	1	3
8	1	4	3	6	9	7	5	2
5	6	3	7	2	1	8	4	9

MANGALDEEP Try Our New Sandal With Sandalwood Oil

PREMIUM QUALITY INCENSE

FOLLOW US FOR MORE CONTENT

आस्था

माता-पिता की मुख्य भूमिका

हमारे जीवन में माता-पिता के महत्व पर धर्म शास्त्रों में बार-बार जोर दिया गया है। आत्मा को मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले उसे जन्म लेना होगा। वेलुकुडी कृष्णन ने एक प्रवचन में कहा, चूंकि हमारे माता-पिता हमारे जन्म के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए वे सम्मान के पात्र हैं।

दूसरे, माता-पिता हमारी रक्षा करते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो वे एक की भूमिका निभाते हैं *पोशाक*—रक्षा करनेवाला। तीसरा, वे वही करते हैं जो हमें पसंद है और जो हमारे लिए अच्छा है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों विरोधाभासी हों। उदाहरण के लिए, एक बच्चा कुछ ऐसा खाना चाह सकता है जो पोषक न हो। माता-पिता उसे जो पसंद है उसका एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे खुश रखते हैं। लेकिन वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा अच्छा भोजन करे, जिससे उसे मजबूती मिलेगी।

जब बच्चे गलती करते हैं तो माता-पिता उन्हें सुधारते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब लोगों ने कोई कानून तोड़ा है, तो माता-पिता तुरंत यह कहते हैं कि उनके बच्चे स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों से गलत धारणाएं सीख ली हैं। बच्चे को सुधारने की कोशिश करते समय भी, माता-पिता बच्चे के आचरण के लिए बहाने बनाते हैं। यह गुण है *वात्सल्य*, जब माता-पिता किसी बच्चे को डांटते हैं या सजा देते हैं तो बच्चे से ज्यादा दर्द माता-पिता को होता है। भगवान नारायण में उपरोक्त सभी गुण हैं।

इसीलिए भगवान और उनकी पत्नी को सार्वभौमिक माता-पिता माना जाता है।

मेंसंकषिप्त



एनएमडीसी ने रिकॉर्ड 45 मीट्रिक टन लोहा दर्ज किया।

अयस्क उत्पादन, 44.5 मीट्रिक टन वित्त वर्ष बिकरी

भारत की सबसे बड़ी लोहा अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने 31 मार्च को समाप्त वर्ष में रिकॉर्ड 45.1 मिलियन टन उत्पादन और 44.48 मीट्रिक टन बिकरी दर्ज की। राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी ने कहा कि वह 45 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली खनन कंपनी बन गई है - जो कि उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। - वार्षिक शारीरिक प्रदर्शन। पिछले पैमाने की तुलना में, जब इसने 40.82 मीट्रिक टन लोहा अयस्क प्राप्त किया था।

उत्पादन और बिकरी 38.22 मीट्रिक टन थी, उत्पादन 10% अधिक था और बिकरी 16% अधिक थी।

इंफोसिस को निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ₹341 करोड़ की कर मांग प्राप्त हुई

आईटी सेवा कंपनी ने सोमवार को कहा कि इंफोसिस को आयकर विभाग से मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए ₹341 करोड़ की कर मांग प्राप्त हुई है, वह उक्त आदेश के खिलाफ अपील का मूल्यांकन कर रही है। बेंगलुरु

मुख्यालय वाली कंपनी ने कहा कि वह 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों पर आदेश के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। इंफोसिस ने यह भी कहा कि वह आदेश के खिलाफ अपील करने का मूल्यांकन कर रही है। 1कीटीआई

प्रचलन में ₹2,000 के बैंक नोटों का मूल्य घटकर ₹8,202 करोड़ हो गया।

प्रचलन में ₹2,000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य, जो 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर ₹3.56 लाख करोड़ था, जब ₹2,000 के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, 29 मार्च को कारोबार की समाप्ति पर घटकर ₹8,202 करोड़ हो गया। 2024, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा। केंद्रीय बैंक ने एक स्थिति अपडेट में कहा, "इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में ₹2,000 के बैंकनोटों में से 97.69% वापस आ गए हैं।"

FY2024 में SUVs की ऑटो बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची, डिस्पैच 42 लाख के पार

परिस दरसट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली

स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग से प्रेरित होकर, भारत में यात्री वाहन की बिक्री वित्त वर्ष 2014 में 42 लाख से अधिक इकाइयों के प्रेषण के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई।

वित्त वर्ष 2024 में निरमाता से डीलरों तक कुल वाहन प्रेषण बढ़कर 42.3 लाख यूनिट हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में 38.9 लाख यूनिट की तुलना में 9% की वृद्धि है।

समग्र यात्री वाहन वितरण में एसयूवी की हिस्सेदारी - वित्त वर्ष 2023 में 43% के मुकाबले वित्त वर्ष 24 में घटकर 50.4% हो गया। मारुति ने कहा, "यह पहली बार है जब भारत में यात्री वाहनों की बिक्री 40 लाख का आंकड़ा पार कर गई है।"



सुजुकी इंडिया (एमएसआई) कार्याकारी समिति के सदस्य शशांक शरीवास्तव, एसयूवी सेगमेंट में साल-दर-साल 28% की वृद्धि हुई; हेचबैक में 12% की वृद्धि; वित्त वर्ष 2014 में सेडान में 6% की वृद्धि हुई, जबकि एमपीवी (बहुउद्देश्यीय वाहन) में 19% और वैन में 6.5% की वृद्धि हुई, शरी शरीवास्तव ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि उद्योग

पैनासोनिक,

आईओसी ने संयुक्त उद्यम पर विचार किया
लिथियम-आयन के लिए
कोशिकाएँ, आँख ई.वी

द हिंदू बयरो

हैदराबाद

राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पैनासोनिक समूह की कंपनी पैनासोनिक एनर्जी कंपनी ने भारत में बेलनाकार लिथियम-आयन कोशिकाओं के निर्माण के लिए अपने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बाध्यकारी टर्म शिट पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त उद्यम को ट-एड के लिए बैटरियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

भारत में तिपहिया वाहन और ऊर्जा भंडारण पूर्णालियाँ। भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनो आरएमएस बैटरी उपयोग प्रौद्योगिकी पर व्यवहार्यता अध्ययन कर रहे हैं।

विस्तारा में पायलटों की अशांति के कारण 49 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं

जागति चंद्रा

नई दिल्ली

एयर इंडिया में विलय से पहले असंतोष काम पर नहीं आने वाले पायलटों के कारण विस्तारा को सोमवार को अपने नेटवर्क पर कम से कम 49 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

विकास के बाद- बाद में, एयरलाइन ने घोषणा की कि उसने अपने द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या को अस्थायी रूप से कम करने का निर्णय लिया है।

'चालक दल की अनुपलब्धता' विस्तारा ने कहा, "पिछले कुछ दिनों में चालक दल की अनुपलब्धता सहित विभिन्न कारणों से हमें बड़ी संख्या में आठ रद्दीकरण और देरी का सामना करना पड़ा है।"



एक बयान। एयरलाइन ने इस मुद्दे पर अपने पहले बयान में कहा, "हम स्थिति को स्थिर करने की दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही अपनी नियमित कृमता का संचालन फिर से शुरू कर देंगे।"

विस्तारा ने कहा कि वह बड़े पैमाने पर भी तेनाती कर रहा है

'पनबिजली अभिलेख सबसे तेज गिरावट चार दशक'

रॉयटर्स

सिंगापुर

भारत का पनबिजली 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान उत्पादन कम से कम 38 वर्षों में सबसे तेज गति से गिरा रॉयटर्सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि अनियमित बारिश के कारण ऊंची मांग के बीच कोयला-लाल बिजली पर निर्भरता बढ़ गई है।

भारत के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा स्रोत से उत्पादन में 16.3% की गिरावट, बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पहली बार गिरावट के साथ हुई, क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में सौर और पवन कृमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।

यात्रियों को समायोजित करने के लिए घरेलू मार्गों पर बोइंग 787-9 और ए321 नियो विमान-इन रद्दीकरणों से एक प्रभाव पड़ता है। एयरलाइन ने कहा कि वह संबंधित ग्राहकों को वैकल्पिक उड़ानें और रिफंड भी प्रदान करेगी।

उद्योग के स्रोतों के अनुसार, नाखुश पायलटों का मौन विरोध, जनशक्ति की कमी के कारण एयरलाइन को पायलट बफर के बिना छोड़ दिया गया है, और खराब रोस्टर योजना को रद्दीकरण के पीछे माना जाता है।

फरवरी में, एयरलाइन ने अपने पायलटों के लिए एक नई वेतन संरचना की घोषणा की। नई संरचना से फरस्ट ऑफिसरस बहुत दुखी हुए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप वेतन में ₹80,000 से ₹1.4 लाख की कटौती हुई।

मार्च का सकल जीएसटी ₹1.78 लाख करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2024 के राजस्व को बढ़ाकर ₹20.2 लाख करोड़ कर देता है।

घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व मार्च में 17.6% बढ़ गया, जो फरवरी की 13.9% वृद्धि से अधिक है; माल आयात से राजस्व, द्वारा एक गणना/हिन्दूगित करता है, फरवरी की 8.5% वृद्धि के बाद, मार्च में साल-दर-साल लगभग 5% सिकुड़ गया

विकास धृत

नई दिल्ली

जीएसटी एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व अपने दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया मार्च में ₹1,78,484 करोड़, जबकि संग्रह में वृद्धि की गति फरवरी से घटकर 11.5% रह गई

12.5%। इसने 2023-24 के लिए टैली को 11.6% बढ़ाकर ₹20.18 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक कर दिया। रिफंड के हिसाब के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व मार्च में 18.4% की तेज गति से बढ़कर ₹1.65 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि फरवरी में इसकी तुलना की गई थी।

Robust takings

Finance Ministry says average monthly collection for FY24 was ₹1.68 lakh crore, beating FY23's average of ₹1.5 lakh crore

<ul style="list-style-type: none"> Gross takings for 2023-24 rise 11.6% to a little over ₹20.18 lakh crore Net GST revenue grew at a faster pace of 18.4% in March to ₹1.65 lakh crore GST Compensation Cess at ₹12,259 crore, was reckoned as the third-highest 	
---	--

13.6% की वृद्धि हुई थी। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए ऋण संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष के औसत ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक है। "औसत मासिक कुल-

द्वारा ने एक बयान में कहा, मार्च में हुई बढ़ोतरी के लिए "घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि" को जिम्मेदार ठहराया।

कुल से राजस्व घरेलू लेनदेन (जो आम तौर पर सेवाओं के आयात पर कर) फरवरी में 13.9% की वृद्धि की तुलना में 17.6% बढ़ गया। जबकि मंत्रालय ने माल आयात से कर के लिए विकास परकषेपवकर साझा नहीं किया, एक गणना/हिन्दूगित करता है कि फरवरी में 8.5% की वृद्धि के बाद, मार्च में राजस्व लगभग 5% कम हो गया।

क्रमिक आधार पर, मार्च का सकल जीएसटी राजस्व

फरवरी से 6% की वृद्धि हुई, और शुद्ध राजस्व 9.3% की वृद्धि हुई। जीएसटी मुआवजा उपकर ₹12,259 करोड़ पर, इसे तीसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह माना गया।

केंद्रीय जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2014 के संशोधित अनुमान से अधिक हो गया, जबकि जीएसटी कृषिपूर्ति उपकर में मामूली कमी थी- ओउज, आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा। वित्त वर्ष 2015 के लिए, "अंतरिम बजट अनुमान को पूरा करने के लिए आवश्यक अंतरनिहित वृद्धि एकल-अंकीय [10% से कम] पर आ गई है, जिसके पार होने की संभावना है," सुश्री नायर ने कहा।

विकास और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने में आरबीआई वैश्विक नेतृत्व कर सकता है: मोदी

ललतेनद मिशर

मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विकास और राशन नियंत्रण में संतुलन की अनूठी उपलब्धि हासिल की है, जो दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है और वैश्विक नेतृत्व ग्रहण कर सकता है।

मुख्य मोदी मंत्री नरेंद्र सोमवार को आरबीआई के 90 के स्मरणोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा। मुंबई में वर्ष रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को कलकत्ता में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में की गई थी और 1 जनवरी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।



नरेंद्र मोदी

1949. संयोग से, श्री मोदी ने 80 में भाग लिया था। four है दिनांक दिवस समारोह में 2014.

"जबकि अनेक देवे-दुनिया के तमाम देश आर्थिक झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं

महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। आरबीआई ने भारत की सफलता को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है," उन्होंने कहा। यह कहते हुए कि राशन नियंत्रण और विकास में संतुलन किसी भी विकासशील देश के लिए एक अनूठी आवश्यकता है, उन्होंने कहा, "आरबीआई इसके लिए एक मॉडल बन गया है और वैश्विक नेतृत्व ले सकता है।"

उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों के लिए आरबीआई को विकास करना चाहिए- लोप मॉडर्न नीति उपकरण भारत के युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे उभरते कृषेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए

प्रयत्न. उन्होंने जोर देकर कहा, "आरबीआई को लीक से हटकर सोचने की जरूरत है।"

उन्होंने बताया कि 2014 में, जब उन्होंने 80 में भाग लिया था। सालगिरह कार्यक्रम में, भारतीय बैंकिंग कृषेत्र की हालत खस्ता थी, उन्होंने कहा कि बढ़ते एनपीए ने बैंकिंग कृषेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है।

"चिंताएँ थी हर तरफ से। लेकिन आज भारत की बैंकिंग व्यवस्था है खुद को मजबूत के रूप में स्थापित किया और टिकाऊ. यह अब विरोध की स्थिति में आ गया है और ऋण में रिकॉर्ड सुधार दिखा रहा है

विकास," उन्होंने आगे कहा।

सेबी अपडेट शिकायत निवारण स्थल निवेशकों के लिए

द हिंदू बयरो

मुंबई

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसई-बीआई) ने प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली - स्कोरस 2.0 - का एक नया संस्करण पेश किया है।

प्रक्रिया हो गई है बनाया अधिक ई साइंट सेबी ने एक बयान में कहा, ऑटो-रूटिंग, ऑटो-एसकेलेशन, नामित निकायों द्वारा निगरानी और समयसीमा में कमी के माध्यम से।

बाज़ार

बाजार देखो

	सोमवार	% परिवर्तन
सेसेक्स	74,015	0.49
सोपा	68,420	1.58
नेस	87.89	

निफ्टी 50

	कीमत	परिवर्तन
अडानी एंर	3252.10	55.00 अडानी
एलए	1375.90	34.05 अडानी
अमृतम	6457.25	100.45 एलए
रेल	2871.00	24.25 एलए
	1053.10	5.90 अडानी
	9042.15	106.00 अडानी
	1646.00	2.15 अडानी
	7250.95	5.70 अडानी
	1217.35	11.25 अडानी
	600.70	1.70 अडानी
इस्टेल	4895.20	16.05 अडानी
	1498.65	1.70 अडानी
इरि	442.05	7.95 अडानी
	3567.95	122.65 अडानी
	6250.35	92.45 अडानी
	3946.65	72.65 अडानी
	2292.55	5.25 अडानी
	1556.70	13.15 अडानी
	1470.50	22.60 अडानी
	634.75	1.40
होने मोटोकॉर	4680.75	41.55
फिलिप	568.00	8.35 अडानी
इरि	2285.90	21.55
अंडीअंडीअंडी	1099.65	
6.35 इस्टेल	1542.40	10.60
इरि	1495.45	2.60
अंडी	426.70	1.65
केरल	871.95	41.75
कोक	1790.70	5.20 अडानी
टी	3838.00	74.10
एलीअंडीअंडी	4882.60	55.80
ए ए ए	1915.95	5.40
मारुति सुकु	12569.60	30.75
मेशु	2385.60	36.75 अडानी
	342.35	6.55
ओएनजीसी	269.90	1.85
पारपर	280.15	3.25
विमान	2969.55	2.15
एलए	1489.95	
10.30 अंडी	758.30	5.95
सूर्य	2431.75	
सिंह	1629.25	8.70
71.95 अडानी	1086.90	
9.30 अंडी	992.25	0.55
टाटा	163.15	7.30
कोक	3916.75	40.45
रेल	1244.55	3.55 अडानी
	3738.40	63.40
अस्टेल	5954.40	205.25
फिलि	484.95	4.85

सीआईएल आउटपुट 10% बढ़ जाता है 2023-24 में कोल इंडिया का उत्पादन 10% बढ़कर 773.6 मिलियन टन (MT) हो गया, लेकिन इसके उत्पादन से कम रहा- 780 मीट्रिक टन का लक्ष्य स्कैन, एक एक्सचेंज लिंग के अनुसार। खनिक ने एक भाषा में कहा, पिछले पैमाने पर उत्पादन 703.2 मीट्रिक टन था। 1कीटीआई

सीआईएल आउटपुट

10% बढ़ जाता है

2023-24 में कोल इंडिया का उत्पादन 10% बढ़कर 773.6 मिलियन टन (MT) हो गया, लेकिन इसके उत्पादन से कम रहा- 780 मीट्रिक टन का लक्ष्य स्कैन, एक एक्सचेंज लिंग के अनुसार। खनिक ने एक भाषा में कहा, पिछले पैमाने पर उत्पादन 703.2 मीट्रिक टन था। 1कीटीआई

THE HINDU GROUP

GIFT THEM LIMITLESS OPPORTUNITIES WITH 21ST CENTURY COMMUNICATION SKILLS

STEP LIVE Junior
NEXT GEN SOFT SKILLS

An interactive English learning course for kids from classes 4-7.

SPEAKING

Strategies to improve public speaking skills with focus on aspects such as persuasion, expression of emotions, etc.

WRITING

Best practices to improve writing structure and introduction to using tools like PowerPoint

LISTENING

Engaging exercises and activities to actively develop listening skills

PRACTICE

Practical tips and guidance to continue developing communication skills

Coach your kids with 10 LIVE classes on various aspects of communication.

Limited Seats!

Summer batch begins on 22nd April

Classes on all weekdays 3:30 pm to 4:30 pm

To develop your child's overall communication skills, visit [BIT.LY/PLUSJUNIOR](https://bit.ly/plusjunior)

Scan the QR code

सोमवार, 2 अप्रैल 2024

स्वीकार

दक्षिणपूर्वी अफगानिस्तान में बारूदी सुरंग विस्फोट में नौ बच्चों की मौत हो गई



एएफपी

एक प्रांतीय अधिकारी ने सोमवार को कहा कि दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में दशकों के संघर्ष के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंग के कारण हुए विस्फोट में नौ बच्चों की मौत हो गई। रविवार को गजनी प्रांत के गेरु जिले में युवा लड़कों और लड़कियों का एक समूह इसके साथ खला रहा था, तभी यह खदान ढह गई। एएफपी

लंडन

यूके का कहना है कि इस सर्दियों में छोटी नावों पर चैनल क्रॉसिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है



गैटी इमेजेज

आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 2024 की पहली विमायी में छोटी नावों से यूके में आगमन ने पिछले साल की तुलना में लगभग 42% की वृद्धि के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिटिश अधिकारियों ने पिछले वर्ष के 3,793 की तुलना में वर्ष के पहले तीन महीनों में 5,373 प्रवासियों को दक्षिणपूर्वी इंग्लैंड के तटी पर उतरने की प्रक्रिया सौंपी। एएफपी

मास्को

रूस ने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के चार और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है



एपी

एक्स-रूस की एएफपी सूत्रों ने कहा है कि रविवार को विक्टोर "आतंकवादी" साजिश में गिरफ्तार किए गए चार लोगों ने पिछले महीने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर घातक हमले के लिए धन और हथियार उपलब्ध कराए थे। 22 मार्च के राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिख रही थी। एएफपी

बाल्टीमोर

बाल्टीमोर के मलबे को साफ़ करने वाले जहाजों के लिए वैकल्पिक मार्ग खोला गया



एपी

एक्स-यूएस कोस्ट गार्ड ने बाल्टीमोर में दह गए प्रॉक्सिमिटी स्कॉट की फ़्लैक के स्थान पर मलबे को साफ करने में शामिल जहाजों के लिए एक अस्थायी वैकल्पिक चैनल खोला, जो बंदरगाह की ओर जाने वाले मुख्य चैनल को बरफबद्ध तरीके से खोलने का हिस्सा था। एक कंटेनर जहाज के टकराने से फ्लैकी पुल होने के बाद पुल ढह गया। एपी

इजराइली सांसदों ने प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को दी मंजूरी अल जज़ीरा

फ़्रांस मीडिया एजेंसी यूरोशलेम

इजरायली संसद ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया, जिसमें शीर्ष मंत्रियों को इजरायल से समाचार चैनल अल जज़ीरा के प्रसारण पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया - एक ऐसा कदम जिससे प्रधान मंत्री बेंजामिन नेता-न्याह उठाने के लिए तैयार हैं।

यह कानून, जो 10 के मुकाबले 70 मतों से पारित हुआ, विदेशी चैनलों से सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है, लेकिन इजरायल में उनके कार्यालयों को बंद करने की भी अनुमति देता है।

इजरायल ने जानुअरी में दावा किया था कि गाजा में हवाई हमले में मारे गए अल जज़ीरा के एक पत्रकार और एक फ्री-लॉन्सर "आतंकवादी संचालक" थे।

अगले महीने इसने कहा कि चैनल का एक अन्य पत्रकार, जो एक अलग हमले में घायल हुआ था, हमला में "डी-प्यूटी कंपनी कमांडर" था।

अल जज़ीरा ने आरोपों से इनकार किया है और इजरायल पर गाजा में अल जज़ीरा के कर्मचारियों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

इज़राइल दो सप्ताह की छापेमारी के बाद शिफ़ा अस्पताल से हट गया

तेल अवीव का दावा है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में उसके ऑपरेशन में लगभग 200 आतंकवादी मारे गए हैं और सैकड़ों को हिरासत में लिया गया है; डब्ल्यूएचओ का कहना है कि छापेमारी के दौरान 20 से अधिक मरीजों की मौत हो गई और दर्जनों को खतरे में डाल दिया गया

संबंधी प्रेस

टीएन-मसलाह

गाजा के इलाके से सरणल की सेना हटी-

दो सप्ताह की छापेमारी के बाद सोमवार तड़के जेरूस अस्पताल में छापेमारी की गई, जिसमें उसने कहा कि उसने लगभग 200 आतंकवादियों को मार गिराया और सैकड़ों अन्य को हिरासत में लिया। फिलिस्तीनी निवासियों ने कहा कि सैनिक अपने पीछे कई शव और भारी मात्रा में विनाश छोड़ गए हैं।

सेना ने शिफ़ा अस्पताल पर छापे को लगभग छह महीने के युद्ध में एक बड़ी जीत बताया है। लेकिन यह इजरायल में बढ़ती विरोध के समय आया, रविवार को हवाई हमलों ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उसने गाजा में रखे गए दर्जनों बंधकों को घर लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की। शुरूआत के बाद से यह सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन था

सेना ने कहा कि शिफ़ा में मारे गए लोगों में हमला के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अन्य आतंकवादी शामिल थे, जो नो-वेम्बर में पहले की छापेमारी के बाद वहां फिर से एकत्र हुए थे, और इसने हथियार और मूल्यांकन सुफ़िया जानकारी जब्त की थी।

युद्ध।

घमासान दिखा



जर्जर स्थिति: सोमवार को इजरायली सेना के हटने के बाद फिलिस्तीनियों ने गाजा के अल-शिफ़ा अस्पताल में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। एएफपी

हमला अभी भी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक में भी प्रतिरोध कर सकता है।

सेना ने कहा कि शिफ़ा में मारे गए लोगों में हमला के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अन्य आतंकवादी शामिल थे, जो नो-वेम्बर में पहले की छापेमारी के बाद वहां फिर से एकत्र हुए थे, और इसने हथियार और मूल्यांकन सुफ़िया जानकारी जब्त की थी।

संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि 20 से अधिक मरीज हैं

जिस घर पर वे रह रहे थे उस घर एक और हमला हुआ।

उन्होंने कहा, "मेरे बाप का घर में नरसंहार हुआ था," "स्थिति अवर्णनीय थी।"

टोल अज्ञात यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि छापे के दौरान कितने फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए।

सेना ने इस बात से इनकार किया कि उसके बलों ने परिसर के अंदर किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाया है।

इजरायल ने हा-मागर पर सैन्य उद्देश्यों के लिए अस्तित्वों का उपयोग करने का आरोप लगाया है और कई चिकित्सा सुविधाओं पर छापा मारा है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारी उन आरोपों से इनकार करते हैं।

आलोचकों ने सेना पर लापरवाही से नागरिकों को खतरे में डालने और पहले से ही युद्ध-घायलों से भरे स्वास्थ्य क्षेत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजरायली सैनिकों ने शिफ़ा के पास रहने वाले सैकड़ों लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर किया।

छापे के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग जोखिम में पड़ गए, जिससे उस अस्पताल में और भी अधिक विनाश हुआ जो पहले ही काफी हद तक काम करना बंद कर चुका था।

बासेल अल-हिलो ने कहा कि उनके सात रिश्तेदारों के शव अस्पताल के आसपास के मलबे में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर पर बमबारी होने के बाद उन्होंने एक पड़ोसी के घर में शरण ली थी, लेकिन फिर



फ़्रांस मीडिया एजेंसी इस्लामुल

इस-तंबुल शहर के चुनाव में एकेम इमामोवुल की दूसरी ठोस जीत उन्हें 2028 के राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिख रही है।

फुटबॉल-प्रेमी 52-वर्षीय, जो पहली बार 2019 में मेगा-सिटी के मेयर बने, ने रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के चुने हुए उम्मीदवार को देना के आर्थिक सत्ता में एक बार फिर हरा दिया, बावजूद इसके कि उन्हें पद से हटाने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था। अनुभवी राष्ट्रपति द्वारा

नेट, पूर्व पर्यावरण मंत्री मुरल कुरम।

2019 में काफी हद तक अज्ञात, श्री इमामोवुल ने उस वर्ष 16 मिलियन की आबादी वाले शहर में श्री एर्दोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) और उसके सहयोगियों के 25 साल के शासन को समाप्त कर दिया, जहां राष्ट्रपति कभी मेयर थे।

छोटी-सी शिवकी, चिकनी-चुपड़ी बातें करने वाले श्रीमान।

जब वोट विवादसद रूप से रह कर दिया गया तो शुरूआत में इमामोवुल ने उनकी जीत जीन ली गई। लेकिन तीन महीने बाद दोबारा डूई दौड़ में उन्होंने और भी बड़े अंतर से जीत हासिल की।

तब से वह तुर्किये के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक बन गए हैं, भले ही उन पर कानूनी कार्रवाई की गई हो।

रविवार के चुनाव में, श्री इमामोवुल सीपघपी उम्मीदवार के रूप में दौड़े क्योंकि वह तुर्किये के खंडित विपक्षी दलों को अपनी बोली के आसपास एकजुट करने में विफल रहे।

उनकी जीत के आकार ने उन पूर्व सहयोगियों को भी चौंका दिया होगा।

अब श्री इमामोवुल को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन की पार्टी के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को हराने के लिए सबसे संभावित संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है।

पाक पीएम ने दिया आश्वासन अचूक सुरक्षा के चीनी नागरिक

प्रेस टूरर ऑफ इंडिया इस्तामनाबाद

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार देश भर में काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए अचूक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगी, देश के अशांत उत्तर-पश्चिम में एक आत्मघाती हमले में पांच चीनी श्रमिकों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद।

पिछले मंगलवार को खैबर-पख्तूनख्वा के सुदूर बैशम इलाके में एक वाहन सवार आत्मघाती हमलावर ने चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को निशाना बनाया, जिसमें पांच चीनी नागरिकों और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई।

"मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि पीए सरकार-

शहबाज की गारंटी पांच दिन बाद आई है

एक आत्मघाती हमले में चीनी कर्मचारी मारे गए

किस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगा, यह सुनिश्चित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा कि आपको और आपके परिवार को सर्वोत्तम संभव सुरक्षा मिले।"

शरीफ ने कोहिस्तान में दासू जलविद्युत परियोजना स्थल पर चीनी श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए एक सभा में यह बात कही।

विस्फोट के सिलसिले में मास्टरमाइंड सहित कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ताइवान में कुत्तों का दिन



ताइपे मास रैपिड ट्रांज़िट के किनारे अपनी पालतू-मैत्रीपूर्ण ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय कुत्ते अपनी घुमक्कड़ी से एक-दूसरे को रूँघते हैं। ताइपे मेट्रो ने रविवार को दिन भर में आठ यात्राओं और मार्ग के सभी सामान्य स्टेशनों पर रुकने वाली दो पालतू-मैत्रीपूर्ण ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। एएफपी

कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान और पत्नी की जेल की सजा निलंबित कर दी

प्रेस टूरर ऑफ इंडिया इस्तामनाबाद

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्थायी राहत देते हुए एक उच्च न्यायालय ने सोमवार को तोशाखाना घटनापर मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया।

आम चुनाव से कुछ दिन पहले राज्य डिपॉजिटरी से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को संकटग्रस्त दंपति को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के अनुसार, श्री खान और सुश्री।

बुशरा को 10 साल तक कोई भी सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया गया और पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रत्येक 787 मिलियन।

उन्होंने इस्लाम-विरोधी उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि को चुनौती दी, जहां आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो सदस्यीय खंडपीठ ने फैसला सुनाया



इमरान खान

आमेर फास्कले ने सुना मामलों। सोमवार को, इस्ताम-विरोधी उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मामले में दंपति की सजा को निलंबित करके और उन्हें मामले में जमानत देकर अस्थायी राहत दी।

हालांकि, अदालत ने घोषणा की कि सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अगले महीने ईद त्योहार के बाद सुनवाई की जाएगी।

लेकिन श्री खान और सुश्री. बुशरा को दोबारा रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अन्य मामलों में दोषी हैं।

जर्मनी ने भांग को विवादास्पद हरी झंडी दे दी है

फ़्रांस मीडिया एजेंसी बर्लिन

विपक्षी राजनेताओं और चिकित्सा संघों की आपत्तियों के बावजूद, सोमवार को जर्मनी में केनबिस की आम भड़क उठी, क्योंकि देश मनोरंजक उपयोग को कानूनी रूप देने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया।

बहुसंघर्षित नए कानून के पहले चरण के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को अब 25 ग्राम सूखी भांग ले जाने और घर पर तीन मारिजुआ-ना पोथे उगाने की अनुमति है।

बदलावों से जर्मनी के कई लोगों के पास कुछ रह गया है



नीदरलैंड, जो नशीली दवाओं के प्रति अपने उदार रवैये के लिए जाना जाता है, ने हाल के वर्षों में केनबिस पर्यटन का मुकाबला करने के लिए सख्त दृष्टिकोण अपनाया है।

पुलिस के अनुसार, जैसे ही आधी रात को कानून लागू हुआ, लगभग 1,500 लोगों ने सेंट्रल बरेलिन में ब्रैंडेनबर्ग गेट के पास लुथी मनाई, साथ ही कुछ लोगों ने जश्न मनाते हुए अपने जोड़ों में रोसनी भी की।

स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटवैबेक ने कहा कि केनबिस की खपत को "वर्जित क्षेत्र" से बाहर लाया गया है

एक्स पर कहा, पूर्व में ट्विटर।

नया कानून था "शर्त-

वास्तविक व्यसन सहायता, बच्चों और युवाओं के लिए रोकथाम और काले बाजार का मुकाबला करने के लिए," श्री लॉटवैबेक ने वैधीकरण के खिलाफ की गई आलोचनाओं का आंशिक रूप से जवाब देते हुए कहा।

कानूनी सुधार के अगले चरण के रूप में, 1 जुलाई से देश में "केन-नाबिस क्लब" के माध्यम से कानूनी रूप से गांजा प्राप्त करना संभव होगा। इन विनियमित संघों में प्रत्येक को 500 तक सदस्य रखने की अनुमति होगी, और वे प्रति व्यक्ति प्रति माह 50 ग्राम तक भांग वितरित करने में सक्षम होंगे।

एक अन्य संभावित मुद्दा केनबिस से संबंधित मामलों पर पूर्वव्यापी माफी का कार्यान्वयन है, जो कानूनी प्रणाली के लिए विधान-प्रशासनिक सिस्टम पैदा कर सकता है।

केना-किस को लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से बेचने की प्रारंभिक योजना यूरोपीय संघ के विरोध के कारण रह कर दी गई थी।

चिकित्सा समूहों ने चिंता जताई है कि वैधीकरण से युवा लोगों में इसके उपयोग में वृद्धि हो सकती है।

इस कानून की भी पुलिस ने आलोचना की है, जिन्हें डर है कि इसे लागू करना मुश्किल होगा।

एक अन्य संभावित मुद्दा केनबिस से संबंधित मामलों पर पूर्वव्यापी माफी का कार्यान्वयन है, जो कानूनी प्रणाली के लिए विधान-प्रशासनिक सिस्टम पैदा कर सकता है।

NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEURO SCIENCES, (An Institute of National Importance, under Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India)
Hosur Road, Bengaluru - 560 029
No.: NIMH/PU-(J)TENDER/RC(24-26)/01 & 02/2023-24 Date: 22.03.2024
TENDER NOTIFICATION
 Online tender is invited from the Primary Manufacturers or Import License Holders (In respect of imported items only) for supply of various kinds of Drugs, Chemicals, Surgical & Miscellaneous items required by the Institute for the period of **24 Months** for the date of issue of Rate Contract. The validity of Rate Contract is from **01.05.2024 to 31.03.2026**. Last date of submission of tender is **17.04.2024**, tenderer can download tender forms from Central Public Procurement Portal (e-procurement Website) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> and submit the tender in online by enclosing the required documents & fee indicated therein. **Tender ID. 1. 2024_NIMHN_799111_2 for Surgical**
2. 2024_NIMHN_800055_1 for Drugs
 Website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> and <https://nimhans.ac.in/> **Sd/-, Director**

विज्ञान

पीआरएल अहमदाबाद के नेतृत्व में टीम ने बृहस्पति के चंद्रमा पर ओजोन की खोज की

वैज्ञानिक वर्तमान में सौर मंडल में विभिन्न खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर रहे हैं जो ओजोन के संकेत दिखाते हैं, स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं और, विस्तार से, उनमें जीवन की मेजबानी करने में सक्षम होने की संभावना है।

Tejasri Gururaj

की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने बृहस्पति के चंद्रमा, कैलिस्टो पर ओजोन की उपस्थिति का संकेत देने वाले मजबूत सबूत खोजे हैं, जो सौर मंडल में बर्फीले खगोलीय पिंडों पर होने वाली जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं।

यह अध्ययन मार्च में प्रकाशित हुआ था इकारस पत्रिका का 2024 अंक। यह 'एसओ2 एस्ट्रोकेमिकल बर्फ' के रासायनिक विकास में शोधकर्ताओं की जांच की रूपरेखा तैयार करता है, जो पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) से बनी बर्फ है।

यह कैलिस्टो की सतह की रासायनिक प्रक्रियाओं और संरचना पर प्रकाश डालता है। विकिरणित बर्फ के नमूनों के सूखी अवशोषण स्पेक्ट्रा के डेटा का विश्लेषण करके, टीम ओजोन के गठन का संकेत देने वाले एक विशिष्ट हस्ताक्षर की पहचान करने में सक्षम थी।

उन्होंने अपनी निष्कर्षों की पुष्टि की कैलिस्टो के पर्यावरण और सौर मंडल में बर्फीले चंद्रमाओं की संभावित रहने की क्षमता को समझने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के साथ उनकी तुलना की गई।

ओजोन का महत्व पृथ्वी पर जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसे यहां उत्पन्न होने का रास्ता मिला; इसके पास पनपने, विकसित होने और विविधता लाने के लिए संसाधन भी हैं। इन संसाधनों में विकिरण की "सही" आवृत्तियों से युक्त सूर्य का प्रकाश, पानी, सही तापमान पर आवश्यक मैसों की स्थिर आपूर्ति प्रदान करने वाला एक स्थिर वातावरण और जीवन-रूपों की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न धार्मिक शामिल हैं।



जुलाई 1979 में वोयाजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा कैलिस्टो की सतह का लगभग वास्तविक रंग में चित्रण किया गया। नासा

अपनी रचना से प्रतिष्ठित। बुध ग्रह जितना बड़ा होने के बावजूद इसका द्रव्यमान आधे से भी कम है। कैलिस्टो मुख्य रूप से पानी की बर्फ, चट्टानी सामग्री, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ कार्बनिक यौगिकों से बना है। ये पदार्थ चंद्रमा को पृथ्वी से परे सौर मंडल में जीवन का समर्थन करने के लिए संभावित उम्मीदवार बनाते हैं।

कैलिस्टो की सतह पर भारी गड्ढे हैं, जो क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं से टकराने के एक लंबे इतिहास का संकेत देता है। (वास्तव में, इसकी सतह सौर मंडल की सबसे पुरानी सतह हो सकती है।) इसमें बृहस्पति के कुछ अन्य चंद्रमाओं, जैसे आयो और यूरोपा पर देखी गई व्यापक भूकंपीय गतिविधि का भी अभाव है।

अपेक्षाकृत कम भूवैज्ञानिक विशेषताओं की उपस्थिति से पता चलता है कि कैलिस्टो की सतह भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय है। दूसरे शब्दों में, इसकी सतह संभवतः लंबे समय तक अपेक्षाकृत स्थिर रही होगी। यह स्थिरता किसी भी उपसतह महासागर या बर्फीली परत के नीचे संभावित आवासीय संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाना कैलिस्टो की सतह ने वैज्ञानिकों की इस टीम को चंद्रमा की सतह की संरचना और गठन की बेहतर समझ हासिल करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

पृथ्वी पर स्थितियों का पुनर्निर्माण भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के परमाणु, आणविक और ऑप्टिकल भौतिकी प्रभाग के आर. रामचन्द्रन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने विकिरण के तहत सल्फर डाइऑक्साइड बर्फ के रासायनिक विकास की जांच की, जिससे ओजोन का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने पहले प्रयोगशाला प्रयोगों में इस प्रक्रिया का प्रदर्शन किया है। वर्तमान टीम का उद्देश्य कैलिस्टो की सतह पर इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों को फिर से बनाना था जब सूरज की रोशनी इसकी सतह पर पड़ती है। ऐसा करने के लिए, शोधकर्ताओं ने वैक्यूम पराबैंगनी का उपयोग किया

कैलिस्टो, अपने प्रभावशाली आकार के बावजूद, है



ओजोन अणु एक साथ बंधे तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। ओजोन परत, पृथ्वी के समताप मंडल के निचले हिस्से में, जमीन से लगभग 15-35 किमी ऊपर पाई जाती है, जो पराबैंगनी विकिरण के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करती है।

फोटॉन, जो चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की नकल करते हैं।

प्रयोग यहां आयोजित किए गए ताइवान में राष्ट्रीय सिंक्रोट्रॉन विकिरण अनुसंधान केंद्र (एनएसआरआरसी), जिसने सूर्य से आने वाले विकिरण को फिर से बनाने के लिए आवश्यक उच्च-ऊर्जा विकिरण स्रोतों तक पहुंच प्रदान की।

कैलिस्टो की सतह का मॉडल बनाने के लिए, शोधकर्ताओं ने सिथियम यूओराइड के एक सस्पेंडेंट को बहुत कम दबाव वाले एक कक्ष में रखा। इस वातावरण ने बाहरी अंतरिक्ष में पाई जाने वाली स्थितियों के समान पुनः निर्माण किया। सल्फर डाइऑक्साइड बर्फ के नमूने सस्पेंडेंट पर जमा किए गए, जिससे अंतिम चरण के लिए चरण तैयार हुआ: अवशोषण स्पेक्ट्रम का अवलोकन।

अवशोषण स्पेक्ट्रम किसी पदार्थ का अद्वितीय फिंगरप्रिंट है। यह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, जो इसकी संरचना और गुणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

टीम ने पूरे प्रयोग के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड बर्फ के नमूनों के तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया।

शुष्क में नमूनों को कम स्तर पर रखा गया था कैलिस्टो की सतह पर स्थितियों के अनुरूप, लगभग 9 K (-264.15 डिग्री C) का तापमान। फिर उन्होंने अलग-अलग पर्यावरणीय परिदृश्यों जैसा दिखने के लिए इसे धीरे-धीरे 120 K तक गर्म किया।

इस प्रक्रिया में, उन्होंने बर्फ को विकिरणित किया वैक्यूम-पराबैंगनी फोटॉन (तरंग दैर्घ्य 137.7 नैनोमीटर) और के साथ

एक फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर का उपयोग करके विकिरण के दौरान और बाद में इसके पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया गया। यह उपकरण फोटॉन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके विद्युत चुम्बकीय विकिरण के निम्न स्तर को मापता है।

ओजोन और संभावित आवास क्षमता पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रम ने सल्फर डाइऑक्साइड बर्फ के नमूनों को विकिरणित करने के बाद ओजोन के गठन का सुझासा किया। यह अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक विशिष्ट हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया था।

शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोगात्मक डेटा की तुलना हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एकल-किंग एंग डेटा से भी की, जिसने 1997 में कैलिस्टो की सतह पर सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन की उपस्थिति का भी सुझाव दिया था।

कैलिस्टो पर ओजोन की खोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चलता है, जो जीवन के लिए आवश्यक जटिल अणुओं (जैसा कि हम इसे जानते हैं) के निर्माण के लिए आवश्यक एक मूलभूत घटक है, जैसे कि अमीनो एसिड, जो चंद्रमा की रहने की क्षमता के बारे में संवात उठाता है। यह हमारे सौर मंडल के अन्य बर्फीले चंद्रमाओं तक फैला हुआ है, जो संभावित रूप से पृथ्वी से परे रहने योग्य स्थितियों के बारे में हमारी समझ को सुधित करता है।

ओजोन के अलावा, शोधकर्ताओं ने अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक अज्ञात बैंड देखा - जैसा कि 1996 में गैनीमेड पर देखा गया था - जो उनकी सतह की संरचना या रासायनिक प्रक्रियाओं में एक सामान्य आणविक स्रोत की ओर इशारा करता है।

यह निष्कर्ष इन चंद्रमाओं पर भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से, यह हमें उन सटीक तंत्रों को समझने में मदद कर सकता है जिनके कारण बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का निर्माण हुआ, जो सक्रिय शोध का विषय बने हुए हैं।

(तेजश्री गुरुराज एक स्वतंत्र विज्ञान लेखक और पत्रकार हैं।)



एक अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 40 वर्षों में गाने के बोल अधिक क्रोधपूर्ण और अधिक आत्म-मूढ़ हो गए हैं। ऑस्टिन नील/अनस्वैश

अध्ययन का कहना है कि गाने के बोल सरल और अधिक दोहराव वाले होते जा रहे हैं

फ़्रांस मीडिया एजेंसी

28 मार्च को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, गाने के बोल वास्तव में सरल और अधिक दोहराव वाले होते जा रहे हैं।

अध्ययन में पाया गया कि पिछले 40 वर्षों में गीत भी क्रोधपूर्ण और अधिक आत्म-मूढ़ हो गए हैं, जिससे हर जगह चिड़चिड़े, उम्रदराज संगीत प्रशंसकों की राय को बल मिला है।

यूरोपीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने 1980 से 2020 तक रेप, कंटी, पॉप, आर एंड बी और रॉक की शैलियों में 12,000 से अधिक अंग्रेजी भाषा के गानों के शब्दों का विश्लेषण किया।

यह बताने से पहले कि गीत कैसे अधिक बुनियादी हो गए हैं, अध्ययन ने बताया कि अमेरिकी गायक-गीतकार महान बॉब डायलन - जो 1960 के दशक में प्रसिद्धि के लिए बढ़े - ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है।

ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक विश्वविद्यालय में सिफारिश प्रणालियों की विशेषज्ञ, वरिष्ठ अध्ययन लेखिका ईवा ज़ैंगरले ने सरल गीतों के कारण किसी नए कलाकार को चुनने से इनकार कर दिया।

लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गीत एक हो सकते हैं "समाज का दर्पण" जो दर्शाता है कि समय के साथ किसी संस्कृति के मूल्य, भावनाएँ और व्यस्तताएँ कैसे बदलती हैं।

40 वर्षों के अध्ययन के दौरान, लोगों के संगीत सुनने के तरीके में बार-बार उथल-पुथल हुई। 1980 के दशक के विनाइल रिकॉर्ड और कैसेट टेप ने 90 के दशक की सीडी को रास्ता दिया, फिर इंटरनेट के आगमन ने आज के एल्बम/डिस्क-संचालित स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को जन्म दिया।

अध्ययन के लिए, जर्नल में प्रकाशित **सकारात्मक, आनंददायक गीतों में कमी आई और क्रोध, घृणा या उदासी की अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई। गीत भी अधिक आत्म-मूढ़ हो गए हैं, 'मैं' जैसे शब्द लोकप्रिय हो गए हैं**

वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्ताओं ने गीतों में व्यक्त भावनाओं की जांच की, कितने अलग और जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें कितनी बार दोहराया गया।

डॉ. ज़ैंगरले ने संक्षेप में कहा, "सभी शैलियों में, गीतों में अधिक सरल और अधिक दोहराव की प्रवृत्ति होती है।"

परिणामों में पिछले शोध की भी पुष्टि की जिसमें समय के साथ सकारात्मक, आनंददायक गीतों में कमी और क्रोध, घृणा या दुःख व्यक्त करने वाले गीतों में वृद्धि देखी गई थी। गीत भी अधिक आत्म-मूढ़ हो गए हैं, "मैं" जैसे शब्द अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।

डॉ. ज़ैंगरले ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में रेप में दोहराव सबसे अधिक बढ़ा है।

शोधकर्ताओं ने यह भी जांच की कि विभिन्न शैलियों के प्रशंसकों ने गीत वेबसाइट जीनियस पर कौन से गाने देखे।

अन्य शैलियों के विपरीत, रॉक प्रशंसक अक्सर नए गीतों के बजाय पुराने गीतों के बोलों को देखते हैं।

एक और तरीका जिससे संगीत बदल गया है डॉ. ज़ैंगरले ने कहा, "शुरुआती 10-15 सेकंड इस बात के लिए अत्यधिक निर्णायक होते हैं कि हम गाना छोड़ते हैं या नहीं।"

उनके अनुसार, पिछले शोध से यह भी पता चला है कि आजकल लोग पृष्ठभूमि में संगीत अधिक सुनते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, अधिक कोरस वाले गाने जो मूल बोल दोहराते हैं, अधिक लोकप्रिय प्रतीत होते हैं।

"गीत आजकल आसान होने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें याद रखना आसान है," डॉ. ज़ैंगरले ने कहा। "यह भी कुछ ऐसा है जिसका अनुभव मुझे रेडियो सुनते समय होता है।"

"विज्ञान" के लिए प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए, कृपया science@thehindu.co.in पर 'दैनिक पृष्ठ' विषय के साथ लिखें।

विज्ञान प्रश्नोत्तरी

क्या सौरमंडल में एलियन जीवन है?

वासुदेवन मुकुंद	पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में इसकी सतह पर तरल पदार्थ का एक पूरा चक्र होता है। पृथ्वी पर, यह पानी से बनी है।	महासागर। चंद्रमा अपनी उपसतह से बर्फ के खोल के माध्यम से छारे पानी और कार्बनिक अणुओं से युक्त कणों को भी अंतरिक्ष में फेंकता है, जो जीवन की संभावना का संकेत देता है।
प्रश्न 1 यह ओलिवियन चंद्रमा सौर मंडल में सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय ग्रह पिंड है, जिससे इस पिंड पर जीवन की संभावना बहुत कम है - लेकिन असांभव नहीं है, खासकर जब से यह सारी गतिविधि इसे कार्की गर्म रखती है। इस चंद्रमा का नाम बताइए।	इस चंद्रमा पर, यह हाइड्रोकार्बन है - और यह जीवन की मेजबानी की संभावना प्रस्तुत करता है।	चंद्रमा का नाम बताएं।
प्रश्न 2 2015-2018 में एक्ज क्विप गैंग डेटा से पता चलता है कि सौर मंडल के सबसे बड़े क्षुद्रग्रह में पानी का एक बड़ा उपसतह महासागर हो सकता है, लेकिन असांभव नहीं है। इसकी सतह पर अभी भी बहुत खारा पानी बहने की उम्मीद है और इसमें सूक्ष्मजीवी जीवन हो सकता है। इस क्षुद्रग्रह का नाम बताइए।	चंद्रमा।	अग्रभाग पर एक छवि में मूल्स - उत्तर: आंख के स्तर पर सयाट दूर्य: मैक्यू पहला संघर्ष: किल्ली निगम चंद्र। के.पन.
प्रश्न 3 यह चंद्रमा एकमात्र ग्रह पिंड है	प्रश्न 5 नासा के अंतरिक्ष यान ने पाया है कि इस सैटेर्नियन चंद्रमा में भूमिगत पानी हो सकता है	विद्युन्मानन योमप्रिया के.



एक्स विजुअल: यह _____ अंतरिक्ष यान के बारे में एक कलाकार की छाप है। नासा ने इसे 2023 में लॉन्च किया था और यह 2031 में बृहस्पति के चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा पर जीवन के संकेतों का अध्ययन करने के लिए पहुंचेगा। रिक्त स्थान में उसका नाम (पूर्व प्रश्न) भरें। ईएसए (सीसी भाषा-एसए आईजीओ 3.0)